PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 197 ● भिलाई, बुधवार 11 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

जनरल नरवणे की किताब पर 'पेंगुइन' का बड़ा बयान

'न छपी, न बिकी', फिर राहुल गांधी तक कैसे पहुंची कॉपी ?

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' ने राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। जहां संसद में राहुल गांधी ने इस किताब की कॉपी दिखाई, वहीं प्रकाशक 'पेंगुइन रैंडम हाउस' ने स्पष्ट किया है कि किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय सब हैरान रह गए जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की एक कॉपी सदन में दिखाई। इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगे कि जो किताब अभी तक बाजार में आई ही नहीं और जिसे आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं किया गया, वह नेता प्रतिपक्ष तक कैसे पहुंची? इस घटना ने न केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को जन्म दिया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विवाद बढ़ता देख पब्लिशिंग कंपनी 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' ने सोमवार को एक कड़ा स्पष्टीकरण जारी किया। प्रकाशक ने साफ तौर पर कहा कि यह किताब अभी प्रकाशन प्रक्रिया में है और इसका कोई भी प्रिंट, डिजिटल या पीडीएफ संस्करण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया, किताब की कोई भी प्रति न तो पेंगुइन द्वारा बेची गई है और न ही किसी को

बांटी गई है। प्रकाशक ने चेतावनी दी है कि यदि इस किताब का कोई भी हिस्सा या पूरी पीडीएफ ऑनलाइन या ऑफलाइन साझा की जा रही है, तो वह सीधे तौर पर कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब कानून का शिकंजा भी कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने किताब के प्री-पब्लिकेशन संस्करण के अवैध प्रसार को लेकर एक एफआईआर (स्न्ढ्क्र) दर्ज की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस किताब की टाइपसेट पीडीएफ कॉपी और फाइनल कवर अवैध रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि सेना के पूर्व प्रमुख की संवेदनशील यादों वाली यह किताब आधिकारिक मंजूरी से पहले ही इंटरनेट पर कैसे लीक हो गई। जनरल एम.एम. नरवणे, जो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे, उनकी यह आत्मकथा उनके करीब चार दशक लंबे सैन्य करियर के अनुभवों का निचोड़ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस किताब में 1962 के बाद भारत और चीन के बीच हुए सबसे भीषण सैन्य टकराव यानी 'गलवान घाटी हिंसा' जैसे अहम घटनाक्रमों का विस्तार से जिक्र किया गया है।

नरवणे ने पेंगुइन के बयान को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने मंगलवार को विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रीपोस्ट किया। इससे पहले प्रकाशन ने कहा था कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति ''मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब पेंगुइन इंडिया के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर लिखा कि किताब की वर्तमान स्थिति यह है। इसी बीच प्रकाशन की ओर से एक अन्य बयान भी जारी किया गया है। जिसमें प्रकाशक ने कहा है कि किसी किताब या उसके प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन हाउस ने कहा है कि प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं हैं।

युवा साथी योजना अप्रैल से

ममता का बड़ा एलान बेरोजगारों को 1500

कोलकाता/ एजेंसी

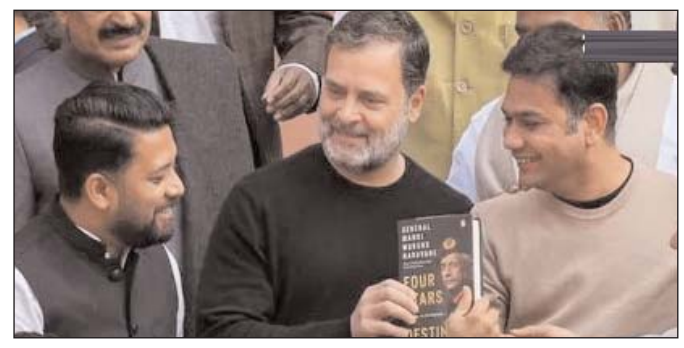

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी सरकार की 'युवासाथी' योजना अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। पहले यह योजना अगस्त में शुरू होने वाली थी। लॉन्च की तारीख आगे बढ़ाने के फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा हमने इसे 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है। इसके साथ ही ममता ने सभी नागरिकों से रमजान और होली के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। बता दें कि राज्य में तीन महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य बजट (अंतरिम) में, हमने तीन से चार स्कीमों की घोषणा की थी।

कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई

पिताजी को मार डाला.....जाकर देख लो बेटी ने हंसिया से काट दिया गला, इस बात से हुई थी खफा, जुर्म भी कबूला

कोरबा। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया के लिममुंडा बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय अशोक कुमार केवट अपने परिवार के साथ रलिया में रहते थे। पिछले आठ वर्षों से उनकी पत्नी और तीन बेटियां कोरबा के आदिले चौक में अलग रह रही थीं। बेटियां निजी कंपनी में काम करती हैं और एक पढ़ाई कर रही है। सोमवार को अशोक केवट की पत्नी और तीनों बेटियां किसी काम से रलिया गांव आई हुई थीं। एक बेटी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसके कारण वे वहीं रुकी हुई थीं। सोमवार की देर रात, बड़ी बेटी गीता केवट (27 वर्ष) और पिता अशोक केवट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गीता ने घर में रखे हसिये से पिता के गले पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद गीता खुद घर से बाहर आकर रिश्तेदारों को बताने

लगी कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। मृतक अशोक केवट के भाई संतोष कुमार ने बताया कि हत्या के बाद गीता बाहर आई और उसने कहा कि पिताजी को मार डाला है, जाकर देख लो। अंदर जाने पर अशोक खून से लथपथ मिले और उनकी मौत हो चुकी थी। गांव के सरपंच विष्णु बिंझवार ने बताया कि अशोक केवट अकेले रहते थे और उनका परिवार कोरबा में रहता था। बताया जा रहा है कि अशोक केवट आदतन शराबी थे और उनकी हरकतों से परेशान होकर पत्नी और बच्चे उनसे अलग रहते थे। मृतक अशोक अक्सर अपनी मां और बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाते थे, जिससे वे परेशान थीं। अशोक राजमिस्त्री का काम करते थे और अकेले ही जीवन यापन कर रहे थे। हरदी बाजार थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।

अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं-अखिलेश

नोएडा/ एजेंसी

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए कथित 'डील' और बजट की प्राथमिकताओं पर सरकार को घेरा। यादव ने कहा कि यह 'डील' नहीं बल्कि 'ढील' साबित हुई है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था और किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बजट आने से पहले और बाद में अमेरिका के साथ हुई 'डील' को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील करने का दावा किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि कितने देश बचे हैं जिनसे ऐसी डील नहीं हुई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस 'डील' के बाद रुपये की स्थिति क्या होगी और पूछा कि अगर यही डील करनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार, यह 'डील' देश के लिए कोई बड़ा लाभ नहीं बल्कि एक प्रकार की 'ढील' है, जिससे देश को यह तय करना होगा कि 18 बड़ा है या जीरो, और बजट पहले बना या डील पहले हुई। यादव ने वर्तमान बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े बजट लाए जा रहे हैं, तो भी प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से फ्री राशन पाने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय बताने की मांग की। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए बजट में किसी खास योजना का उल्लेख न होने पर भी अखिलेश यादव ने असंतोष व्यक्त किया।

तेजस्वी यादव ने जमीन के बदले नौकरी केस में आरोप स्वीकार करने से किया इनकार

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीबीआई की जांच वाले जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अपने खिलाफ कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मामले में मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और अन्य कई आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया और सरकारी नौकरियों को जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया।

विधानसभा पहुंच विरोधियों को दिया संदेश

अध्यक्ष बनने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे विधायकी-नितिन नबीन

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और अपनी भावी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। सदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संगठन की बड़ी जिम्मेदारी के साथ-साथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते रहेंगे। नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्तरदायित्व सौंपा है, उसे वे पूरी मजबूती से निभाएंगे, लेकिन अपनी जड़ों और बांकीपुर की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सर्वोपरि रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वे हर हाल में खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि उनका मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारना और संगठन को पंचायत स्तर तक और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और बिहार के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति भी जो मेरी जिम्मेदारी है, उसे भी पूरा करूंगा।

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

118 विपक्षी सांसदों ने किए साइन, क्या रचा जाएगा इतिहास

नई दिल्ली/ एजेंसी

विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। स्पीकर के खिलाफ 118 सांसद एकजुट हैं। मंगलवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की अगुवाई में लोकसभा सचिवालय को प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस प्रस्ताव में विपक्ष के साथ नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई कांग्रेस चीफ व्हिप कोडिकुन्निल सुरेश, सांसद मोहम्मद जावेद और अन्य ने यह नोटिस लोकसभा सचिवालय को दिया। नोटिस देने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव की जांच करने और प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों के 118 सांसदों ने साइन किए हैं। प्रस्ताव से जुड़ा यह नोटिस संविधान के आर्टिकल 94(ष) के तहत लोकसभा सेक्रेटेरिएट को दिया गया है। अब लोकसभा सचिवालय अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय करेगा। संसद के बजट सत्र के दौरान 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे के अप्रकाशित मेमोयर का जिक्र किया। जिसके बाद सत्ता पक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी अप्रकाशित किताब पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर बोलने से रोक दिया। ओम

बिरला ने राहुल गांधी को कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी अपनी जिद पर अड़े रहे और बोलने से इनकार कर दिया। और राहुल गांधी का भाषण सदन की कार्यवाही से हटा दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अन्य विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका दिया तो उन्होंने भी विरोध दर्ज कराते हुए बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आसन की तरफ कागज उछाले गए। जिसके चलते आठ विपक्षी सांसदों सस्पेंड कर दिया गया। इस गतिरोध को लेकर विपक्ष का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, जबकि सत्ता में बैठे लोगों को पूरी छूट दी जाती है। पहला प्रस्ताव: 18 दिसंबर 1954 को तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसे बहस के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरा प्रस्ताव: 24 नवंबर 1966 को स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ मोशन लाया गया था। हालांकि, 50 से कम सदस्यों ने इसका समर्थन किया, इसलिए मोशन गिर गया। तीसरा प्रस्ताव: 15 अप्रैल 1987 को उस समय के लोकसभा स्पीकर बलराम झाखड़ के खिलाफ मोशन लाया गया था। इसे भी बहस के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर राहुल गांधी ने ही नहीं किए हस्ताक्षर, पार्टी ने बताई ये वजह

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का हस्ताक्षर करना संसदीय लोकतंत्र में सही नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

संक्षिप्त समाचार

मंदिर की छत गिरी, प्रसाद लेने गईं 3 बच्चियों की मौत

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैलारस क्षेत्र के एहरौली गांव स्थित चामड़ माता मंदिर में अचानक छत भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त मंदिर में प्रसाद लेने गईं 3 मासूम बच्चियों की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दंपति और तीन अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंदिर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के दौरान अचानक छत टूटकर नीचे गिर गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मलबे में दबने से तीन बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है। फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। प्रारंभिक तौर पर मंदिर की पुरानी और जर्जर छत को हादसे की वजह माना जा रहा है।

मणिपुर के उखरुल में फिर हिंसा भड़की 21 घर फूंके गए, फायरिंग से दहशत

उखरुल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। मामूली विवाद के बाद भड़की इस हिंसा में अब तक 21 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। हथियारबंद बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई, जिसके चलते कई ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार दोपहर लिटन सरेखोंग गांव में कथित तौर पर हथियारबंद लोगों ने कई घरों में आग लगा दी और हवा में गोलियां चलाईं। हालात बिगड़ते देख ग्रामीण जरूरी सामान लेकर पड़ोसी जिला कांगपोकपी के सुरक्षित इलाकों में चले गए। हिंसा के चलते तांगखुल समुदाय के कई लोगों ने भी अपने घर छोड़ दिए हैं। बताया गया है कि इस हिंसा की शुरुआत शनिवार रात हुई थी, जब लिटन गांव में सात-आठ लोगों ने तांगखुल नागा समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला किया था।

आयोध्या में धमाके की साजिश रचने वाले आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले की जेल में बंद 20 वर्षीय आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, यह हमला जेल में ही हुआ, जहां एक अन्य कैदी ने नुकीली चीज से उसके सिर पर हमला किया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हमलावर का नाम अरुण चौधरी है, जो कश्मीरी युवक है। रविवार रात को उसने अब्दुल रहमान पर हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

CMYK

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तेंदूपत्ता शाखकर्तन एवं अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का किया आयोजन

जगदलपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सरगीपाल काष्ठागार डिपो, जगदलपुर में तेंदूपत्ता शाखकर्तन (बूटा कटाई) एवं अग्नि सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक जगदलपुर किरण देव उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य तेंदूपत्ता उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, वैज्ञानिक पद्धति से शाखकर्तन की जानकारी देना और वनाग्नि से होने वाले नुकसान की रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाना था। मुख्य अतिथि ने वन संरक्षण, तेंदूपत्ता संग्राहकों की भूमिका और अग्नि सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी बस्तर उत्तम कुमार गुप्ता, उप वन मंडलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा, उप वन मंडलाधिकारी बस्तर इंद्र प्रसाद बंजारे, उप वन मंडलाधिकारी चित्रकोट योगेश कुमार रात्रे, उपप्रबंध संचालक जिला यूनियन जगदलपुर गुलशन कुमार साहू, प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक शिवेंद्र सिंह एवं समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर वनमंडल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा तेंदूपत्ता की सही समय पर और उचित विधि से बूटा कटाई करने की तकनीक, उसके लाभ और वन संरक्षण पर इसके सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में संभावित वनाग्नि की रोकथाम, प्रारंभिक आग नियंत्रण उपाय एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक जानकारियां भी साझा की गईं। इस अवसर पर गत वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फड़मुंशियों को गेंदे की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही चक्रीय निधि से लोन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों, स्व सहायता समूह एवं बीमा लाभ प्राप्त करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को डेमो चेक माननीय मुख्य अतिथि किरण देव के करकमलों से प्रदान किया गया। इससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल को बल मिला। कार्यशाला में समस्त फड़ मुंशी, समस्त फड़ अभिरक्षक, समस्त पोषक अधिकारी, समस्त प्रबंधक एवं समस्त अस्थायी अग्नि प्रहरी भी उपस्थित थे। प्रतिभागियों से वनाग्नि की घटनाओं की तत्काल सूचना देने और सामूहिक प्रयासों से वन एवं पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की गई। कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। यह कार्यशाला वन संरक्षण, आजीविका संवर्धन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल के रूप में दर्ज की गई।

धान नहीं बिकने के विरोध में कर्रा सोसायटी क्षेत्र के किसान धरने पर

धान नहीं बिकने के विरोध में कर्रा सोसायटी क्षेत्र के किसान धरने पर, तीसरे दिन भी जारी आंदोलन, धान उठाव रोका, कांग्रेस व कृषक चेतना मंच ने दिया समर्थन

जांजगीर-चांपा। धान खरीदी नहीं होने से आक्रोशित कर्रा सोसायटी अंतर्गत ग्राम हरदी, दहिदा, कर्रा, बरबसपुर और आमानारा के किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। नाराज किसानों ने धान उठाव को रोक दिया है, जहां खरीदी केंद्र के भीतर ट्रक खड़े हैं, वहीं किसान केंद्र के बाहर डेरा डालकर धरना दे रहे हैं।किसानों का कहना है कि शासन द्वारा बनाए गए नए नियमों के चलते उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी धान खरीदी नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

किसानों के समर्थन में कृषक चेतना मंच भी धरने पर बैठ गया है और शासन की नीति का विरोध कर रहा है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में धान खरीदी बंद होना उसकी समस्याओं को और बढ़ा रहा है।धरनास्थल पर पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव सिंह ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि,÷इस सरकार में किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। धान नहीं खरीदने के लिए तरह-तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। धान खरीदी तत्काल फिर से शुरू की जाए और जिन किसानों का धान किसी भी कारणवश नहीं बिक पाया है, उनका धान भी लिया जाए।÷ किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस मामले मे क्या निर्णय लेती है।

रातभर चले विशेष अभियान में पुलिस ने 10 वारंटियों को किया गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से जांजगीरङ्कचांपा पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 08 फरवरी 2026 की दरम्यानी रात पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 10 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत थाना जांजगीर से 04 गिरफ्तारी वारंटी, थाना बलौदा से 01 गिरफ्तारी वारंटी, थाना पामगढ़ से 01 गिरफ्तारी वारंटी, थाना नवागढ़ से 01 गिरफ्तारी वारंटी, थाना शिवरीनारायण से 01 स्थाई वारंटी, थाना बिर्रा से 02 गिरफ्तारी वारंटी एवं 01 स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार एक ही रात में कुल 08 गिरफ्तारी वारंटी एवं 02 स्थाई वारंटी सहित 10 फरार वारंटियों को पुलिस ने दबोच लिया। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप, एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार तथा सीएसपी जांजगीर योगिताबाली खापर्डे के कुशल मार्गदर्शन में संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस बल की सक्रिय सहभागिता से संपन्न हुई। रातभर चले इस विशेष अभियान में पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ कार्य किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी से जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जांजगीर-चांपा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के सघन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

15 करोड़ 86 लाख की लागत से बनेगा हसदेव नदी पर नया पुल विधायक व्यास कश्यप के प्रयासों से मिली स्वीकृति, जाम से मिलेगी राहत

चाम्पा। हसदेव नदी पर लंबे समय से प्रस्तावित नए पुल के निर्माण की मांग अब पूरी होने जा रही है। जनता की निरंतर मांग और जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप के अथक प्रयासों से शासन ने नए पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यह पुल लगभग 15 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया जाएगा। नए पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और रोजाना लगने वाले घंटों के जाम से आम जनता को राहत मिलेगी। वर्तमान में संकरी पुलिया और बढ़ते यातायात दबाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल निर्माण की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीते दिनों निर्माण स्थल पर बने बेजा कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें लछनपुरङ्कबिरगहनी मार्ग पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पांच दुकानों को तोड़ा गया, वहीं एक फैक्ट्री को भी हटाकर पुल निर्माण का रास्ता साफ किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, शासन के नियमानुसार किसी भी बड़े निर्माण कार्य के लिए कम से कम 90 प्रतिशत लैंड क्लियरेंस आवश्यक होता है। बेजा कब्जा हटाओ अभियान के बाद पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। नदी के दूसरी ओर अब केवल करीब 10 प्रतिशत अतिक्रमण शेष है, जिसे हटाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।अधिकारियों ने बताया कि नए पुल का डिजाइन तैयार किया जा चुका है और मिली जानकारी के अनुसार सभी तकनीकी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

'कलेक्टर के निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, 7 हाईवा वाहन जब्त

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। तहसील बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम पूछेली क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते पाए गए 7 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया।जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार खनिज विभाग एवं पुलिस बल को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर महोबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जिला टास्क फोर्स द्वारा सतत निगरानी रखते हुए आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

कबीरधाम जिले के प्रतिष्ठित समाजसेवी भगतराम पटेल राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य नियुक्त

कवर्धा। कबीरधाम जिले के समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भगतराम पटेल को राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के माध्यम से की गई है। उनकी नियुक्ति को जिले सहित पूरे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। भगतराम पटेल लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनसेवा, सामाजिक न्याय एवं लोकहित के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देते आ रहे हैं। उनकी निष्पक्ष छवि, प्रशासनिक समझ और समाज के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने पटेल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। शर्मा ने कहा कि भगतराम पटेल जैसे अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति से राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण और अधिक सशक्त होगा तथा आम नागरिकों का विश्वास व्यवस्था में और मजबूत होगा। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि पटेल अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ करेंगे और पुलिस व्यवस्था को जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भगतराम पटेल की इस नियुक्ति पर जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों ने शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।

कवर्धा शहर में गोगो पेपर सहित प्रतिबंधित नशीली सामग्री के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की सख्त और व्यापक कार्रवाई

कवर्धा शहर के प्रमुख बाजारों, पान ठेलों एवं दुकानों में एक साथ सघन एवं औचक जांच अभियान चलाया गया।

कवर्धा। गोगो पेपर सहित अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री की बिक्री पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही सामग्री जब्त की गई। दोबारा प्रतिबंधित नशे के लिए उपयोग वाली सामग्री की बिक्री पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी दी गई। युवाओं को नशे से दूर रखने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु कबीरधाम पुलिस द्वारा निरंतर और प्रभावी अभियान जारी है।कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के कुशल मार्गदर्शन में कवर्धा शहर में अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली सामग्री के विरुद्ध सघन और सुनियोजित अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना तथा शहर में नशे के अवैध कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाना रहा।अभियान के तहत डीएसपी कृष्णा चंद्राकर के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी योगेश कश्यप एवं पुलिस टीम द्वारा कवर्धा शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों, पान ठेलों, किराना दुकानों एवं अस्थायी ठेलों में लगातार औचक निरीक्षण एवं गहन जांच की गई। पुलिस टीम ने पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ प्रत्येक संदिग्ध स्थल की बारीकी से तलाशी ली। जांच के दौरान कई दुकानों एवं ठेलों से गोगो पेपर तथा अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर ही जब्त करते हुए संबंधित संचालकों को थाना लाया गया। संबंधित दुकानदारों एवं ठेला संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित नशीली सामग्री का विक्रय पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रकरण दर्ज कर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई शामिल होगी। डीएसपी कृष्णा चंद्राकर ने बताया कि कबीरधाम पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए इस प्रकार की सघन एवं प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि नशे से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

कन्या महाविद्यालय सूरजपुर की छात्राओं ने राज्य स्तरीय सात दिवसीय रा.से.यो. शिविर में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

सूरजपुर। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.) इकाई की छात्राएँ उपासना गोयन एवं बिमला पैकरा ने छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विशेष सात दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में सहभागिता कर जिले एवं विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। यह शिविर बलौदा बाजारङ्कभाटापारा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से चयनित स्वयंसेवकों ने भाग लिया। शिविर के दौरान समाज सेवा, सामुदायिक सहभागिता, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता तथा अनुशासन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। छात्राओं ने इन सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रभावी प्रदर्शन किया। विशेष रूप से आयोजित रुमाल झपट्टा प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान तथा तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर उन्होंने सूरजपुर जिले और विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया।इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य बृजलाल साहू एवं रा.से.यो. इकाई की कार्यक्रम अधिकारी पूजांजली भगत ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियाँ विद्यार्थियों को समाज सेवा के प्रति प्रेरित करती हैं और महाविद्यालय की शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक परंपरा को सुदृढ़ बनाती हैं।

मजबूत कानून, सुरक्षित अधिकार' के संदेश के साथ वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 का व्यापक प्रचार-प्रसार

जिले के सभी ग्राम पंचायत में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का संयुक्त आयोजन

अंबिकापुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अंबिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत हर्राटिकरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में 'मजबूत कानून, सुरक्षित अधिकार' के संदेश के साथ वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जिले में नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देने, जनजागरूकता बढ़ाने तथा शासन की योजनाओं से जोड़ने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वीबी-जी राम जी अधिनियम से संबंधित जागरूकता पंपलेट का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत हर्राटिकरा की सरपंच श्रीमती अमृता पैंकरा ने कहा कि हमारे गांव में आज रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाया गया। वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए। रोजगार दिवस के अवसर पर लोगों को 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार के प्रावधान के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि गांव का हर पात्र परिवार योजनाओं का पूरा लाभ ले और समय पर आवास निर्माण व रोजगार कार्यों में जुड़ सके। रोजगार दिवस पर जी राम जी अंतर्गत कार्यों, मजदूरी भुगतान एवं रोजगार मांग पंजीयन की प्रक्रिया समझाई गई। आवास दिवस के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा कर हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया। लंबित किश्तों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केवाईसी पूर्ण कराने और 7 दिवस के भीतर किश्त भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी व सामग्री संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय भागीदारों के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 की जानकारी भी दी गई, ताकि हितग्राही अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संपर्क कर सकें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

सूरजपुर। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा सेवा प्रदाय तंत्र की समग्र प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एवं भुगतान की स्थिति पर सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण किए जाएं। निर्माणाधीन आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने हेतु नियमित मॉनिटरिंग एवं भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया।बैठक में जिले में स्थापित प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के सुचारु संचालन पर चर्चा करते हुए मल्टीलेयर प्लास्टिक के नियमित संग्रहण एवं वैज्ञानिक प्रसंस्करण के निर्देश दिए गए, ताकि जिले को स्वच्छ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों, उद्देश्यों एवं समेकित कार्ययोजना पर चर्चा की गई। अधिनियम से आमजन को परिचित कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार, ग्राम सभा, आवास दिवस एवं रोजगार दिवस के माध्यम से योजनाबद्ध गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले, समस्त जनपद सीईओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

लाल सिग्नल तोड़ने, नशे में ड्राइविंग और फर्जी प्रेस कार्ड पर दुर्ग यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई

रायपुर। यातायात नियमों की अनदेखी कर लाल बत्ती पार करने, नशे की हालत में वाहन चलाने और फर्जी पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश एक वाहन चालक को भारी पड़ गई। मामला दुर्ग शहर का है, जहां यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, 3 फरवरी को नियमित पेट्रोलिंग के दौरान नेहरू नगर चौक पर तैनात यातायात टीम ने एक स्विफ्ट कार को लाल सिग्नल तोड़ते देखा। चालक वाहन में अनाधिकृत हूटर/सायरन का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल पार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तुरंत वाहन को रुकवाया। जांच के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध लगने पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें वह शराब के नशे में पाया गया। वाहन में लगे सायरन भी नियमों के विरुद्ध पाए गए। इसी बीच चालक ने खुद को पत्रकार बताते हुए एक प्रेस कार्ड दिखाकर पुलिस कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, लेकिन जांच में वह पहचान पत्र फर्जी निकला। पुलिस ने किसी भी दबाव को दरकिनार करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई जारी रखी। चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक ड्राइविंग) और 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन उपयोग) के तहत मामला दर्ज कर चालान किया गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं, ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और नियमों के विरुद्ध उपकरण या फर्जी पहचान पत्र का उपयोग न करें। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन ही सड़क सुरक्षा की कुंजी है।

दुर्ग में नशे में ड्राइविंग पर सख्ती, विशेष अभियान में 9 चालक पकड़े गए

रायपुर। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 8 फरवरी की शाम से देर रात तक जिले के प्रमुख चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर जांच नाके लगाए गए। ब्रीथ एनालाइजर मशीन से की गई जांच में कुल 9 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। इनमें एक एम्बुलेंस चालक भी शामिल था, जिसे नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा जाना बेहद गंभीर माना जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर मामला न्यायालय में पेश किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों, खासकर आपातकालीन सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर खुद और दूसरों की जान सुरक्षित रखें।

घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

रायपुर। लालबाग थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और धारदार हथियार दिखाकर धमकाने के मामले में पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला राजनांदगांव जिले के पेण्ड्री इलाके का है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी टुकेश के घर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से मारपीट की। आरोपियों ने चाकूनुमा कटारी दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी करीम मुगल उर्फ बबलू (28 वर्ष) को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस और जुआ एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

पाटन क्षेत्र में चोरी गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पाटन थाना क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में हुई 8 चोरी की वारदातों का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नाकाबंदी, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर रायपुर के मठ पुरैना इलाके से तीन मुख्य आरोपियों—मनीष अमोरिया, जितेंद्र गायकवाड़ और रवि साहू—को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने सुनसान मकानों की रेकी कर चोरी करना स्वीकार किया। आगे की जांच में तीन खरीदारों—धर्मेंद्र साहू, उमेश उर्फ पिंटू सोनी और प्रकाश सोनी—को भी गिरफ्तार किया गया। गिरोह द्वारा नंदनी, रानीतराई, उतई, अमलेश्वर और पाटन क्षेत्रों में अलग-अलग तारीखों पर सूने मकानों को निशाना बनाया गया था।

विजेता दलों से मिलकर बढ़ाया उत्साह

अमित शाह ने देखा बस्तर की जनजातीय विरासत का वैभव

- बस्तर पंडुम में दिखी आदिवासी जीवन की झलक, प्रदर्शनी देखकर मंत्रमुग्ध हुए केंद्रीय गृहमंत्री
- जनजातीय संस्कृति की अनूठी पहचान बना बस्तर पंडुम, विजेताओं को मिला सम्मान

रायपुर/ संवाददाता

संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय समाज के जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों,

हस्तशिल्प और कलाओं की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस व लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण, तुम्बा कला, जनजातीय चित्रकला, वन औषधि, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति भारत की आत्मा का जीवंत स्वरूप है। प्रदर्शनी में दंडामी माड़िया, अबूझमाड़िया, मुरिया, भतरा एवं हल्बा जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। जनजातीय चित्रकला के माध्यम से आदिवासी जीवन, प्रकृति और परंपराओं की सजीव झलक प्रस्तुत की गई। वहीं, वैद्यराज द्वारा वन औषधियों का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया। स्थानीय व्यंजन स्टॉल में जोंधरी लाई के लड्डू, मंडिया पेज, आमट, चापड़ा चटनी, कुलथी दाल, पान बोबो, तीखुर जैसे पारंपरिक व्यंजन तथा लांदा और सल्फी पेय पदार्थ प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर पंडुम जनजातीय संस्कृति को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार जनजातीय कला, शिल्प और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पंडुम की बारह विधाओं की प्रतियोगिता में विजेता दलों से भेंट कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बस्तर संभाग की गौरवशाली संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण हेतु आयोजित 'बस्तर पंडुम 2026' में सुकमा जिले ने सफलता का परचम लहराया है। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित इस भव्य संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सुकमा के जनजातीय नाट्य दल विधा को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के कलाकारों को स्मृति चिन्ह और 50 हजार रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया।

टाटीबंध में बना प्रदेश का सबसे आधुनिक महतारी सदन सह आंगनबाड़ी

- 85 लाख की लागत से तैयार 4500 वर्गफुट का अत्याधुनिक केंद
- बच्चों के लिए खेल-खेल में शिक्षा और माताओं के लिए सम्मानजनक सुविधाएँ

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास अब केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मानवीय संवेदना और भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विधायक राजेश मूणत की पहल पर शहीद भगत सिंह वार्ड, टाटीबंध में प्रदेश का सर्वसुविधायुक्त 'महतारी सदन सह आंगनबाड़ी केंद्र' पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। लगभग 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित और 4500 वर्गफुट में फैला यह केंद्र छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी व्यवस्था में एक नई पहचान स्थापित करेगा। यह भवन पोषण, शिक्षा और संस्कार का संगम बनकर माताओं एवं नौनिहालों को सुरक्षित, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण उपलब्ध कराएगा। इस अत्याधुनिक महतारी सदन में पृथक प्ले-एरिया, डिजिटल लर्निंग के अनुकूल कक्षाएँ, स्वच्छ किचन, डाइनिंग एरिया, स्टोर रूम एवं प्रशासनिक कार्यालय की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही महिला, पुरुष एवं दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग वाशरूम, आकर्षक पेवर ब्लॉक और सुरक्षित बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ फिसलपट्टी, झूला, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, सांप-सीढ़ी एवं अन्य खेलों की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र अब केवल आंगनबाड़ी नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक 'ग्रोथ सेंटर' के रूप में कार्य करेगा। रायपुर पश्चिम में ऐसे चार आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र शीघ्र ही लोकार्पण के लिए तैयार हैं।

नवा रायपुर का सफर होगा आसान, अगले 6 महीने में दौड़ेंगी 40 ई-बसें

रायपुर। संवाददाता

मंत्रालय के कर्मचारियों और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर से नवा रायपुर के बीच अगले छह महीनों में ई-बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हो रही है, जिससे नवा रायपुर में आवागमन सुगम होगा और वहां की बसाहट को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को भी बल मिलेगा। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाले लोगों के लिए पिछले सात-आठ वर्षों से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। प्रशासन ने रायपुर और नवा रायपुर को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड को चुना है। कंपनी को 73.80 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टेंडर दिया गया है। अनुबंध के अनुसार, वर्कआर्डर मिलने के छह महीनों के भीतर ई-बसें सड़कों पर दिखाई देने लगेंगी। यह अनुबंध 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है, जिससे परिवहन व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। ई-बसों के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचे पर भी काम शुरू हो चुका है। एनआरडीए ने चीचा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक डिपो का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस डिपो में बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए विशेष वर्कशाप के साथ ही बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पाइंट भी स्थापित किए जाएंगे। बसों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, ताकि लाइव मानिटरिंग की जा सके। नई ई-बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल होंगी, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्नत होंगी।

जिला बाल संरक्षण की टीम द्वारा रोकवाई गई दो नाबालिको का विवाह

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे-सांसद अग्रवाल

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ जैसे विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने वाले राज्य देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यह कहना है लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का। जिन्होंने बुधवार को लोकसभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और पारदर्शिता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' की जमीनी पहुंच और खाद्यान्न के रिसाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों

पर जवाब मांगा। डिजिटल तकनीक से रुका भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में 2.7 करोड़ लोग लाभान्वित चर्चा के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 82 लाख से अधिक राशन कार्ड सक्रिय हैं, जिनके जरिए लगभग 2.7 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 99.9त्न राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' और 'मेरा राशन ऐप' जैसी डिजिटल पहलों ने वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया है। छत्तीसगढ़ को मिली रिकॉर्ड खाद्य सब्सिडी बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई भारी-भरकम सब्सिडी का विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ को पिछले वर्षों में निरंतर वित्तीय सहयोग मिला है।

सरगबंद तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 50.77 लाख तथा 3 सामुदायिक भवनों के लिए 59.77 लाख मंजूर

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका में 14 कार्यों के लिए दो करोड़ 88 लाख 10 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से राशि की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कटघोरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-15 में बरभांठा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 14 लाख 92 हजार, मरखीमाता मंदिर के पास शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए तथा नाली निर्माण के लिए 3 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-2 में रेस्ट हाउस बाउंड्रीवॉल से मेला ग्राउंड तक सीसी रोड के लिए 19 लाख रुपए, बी.आर. अंबेडकर भवन में बाउंड्रीवॉल के लिए 24 लाख 75 हजार रुपए, बीएसएनएल ऑफिस से बी.आर. अंबेडकर भवन तक सीसी रोड के लिए 28 लाख 32 हजार रुपए।

वीबी जी रामजी योजना से गांव-गांव पहुंचेगा रोजगार

रायपुर/ संवाददाता

शासन की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी (वीबी जी राम जी) योजना के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को रोजगार दिवस, चावल उत्सव और आवास दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जिसे अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 125 दिनों तक किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक रोजगार के अवसर पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को क्यूआर कोड आधारित नई प्रणाली की जानकारी दी गई। अब जॉब कार्ड और मस्टर रोल का मिलान क्यूआर कोड स्कैन कर किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और गड़बड़ी की संभावना कम हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के नामों का वाचन किया गया तथा आवास निर्माण के लिए मिलने वाली किश्तों, मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री और अन्य विभागों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने हितग्राहियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण पूरा करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया।

उद्योग मंत्री ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात

छत्तीसगढ़ की साय सरकार सभी समाज के साथ खड़ी-मंत्री

- मुड़ापार हेलीपेड में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का कैबिनेट मंत्री और महापौर ने फीता काटकर किया लोकार्पण

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने रविवार को मुड़ापार, हेलीपेड में मथुरा माली मरार पटेल समाज को 10 लाख की लागत से बने सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन की सौगात दी। कार्यक्रम में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने समाज के पदाधिकारियों के साथ मां शाकम्भरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और शहर की खुशहाली की कामना की नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि सभी समाज की आर्थिक उत्थान और प्रगति के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार सभी समाज के साथ खड़ी है और उनके उत्थान और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। कोरबा विधानसभा में भी सभी समाज की मांग अनुरूप विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मथुरा माली मरार पटेल समाज का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, समाज की सेवा करने का मुझे यह सौभाग्य मिला है। समाज की मांग पर प्रभारी मंत्री मद से 10 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया गया है, आज भवन समाज को समर्पित किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ वार्ड क्रमांक 55 सुमेधा नागिन भाटा में समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 10 लाख की स्वीकृति दी गई है, जल्द ही भवन पूर्ण हो

जाएगा। मथुरा माली मरार पटेल समाज के समाज के सभी प्रमुख जनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि पटेल समाज एक संगठित और सशक्त समाज है। समाज एक सशक्त और संगठित समाज की अवधारणा को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। पटेल समाज एक मेहनतकश समाज है। कड़ी मेहनत कर धरती को हरा भरा बनाने का कार्य मरार समाज करता है। उन्होंने कहा कि समाज आज खेती किसानी, सब्जी-भाजी के उत्पादन के साथ- साथ हर क्षेत्र में काफी आगे है। इस अवसर पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर, एमआइसी सदस्य श्रीमती धन कुमारी गर्ग, पार्षद ईश्वर पटेल, पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन, पार्षद श्री मुकुंद कंवर, कोरबा मंडल अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा, श्री रामकृष्ण साहू, श्रीमती स्मिता सिंह, श्रीमती पूर्णिमा पासवान, श्री नवनीत शुक्ला, श्री सुकेश दलाल, श्रीमती संगीता साहू, श्री अनुज यादव व समाज के प्रमुख, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की नेतृत्व में कोरबा शहर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। शहर के वार्ड, बस्तियों के मूलभूत विकास कार्य की बात हो, या फिर बड़े निर्माण कार्यों की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण सभी समाज को उनके मांग अनुरूप विकास कार्यों की सौगात देने की बात हो।

संपादकीय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से राहत की उम्मीद, पर कई सवाल अब भी बाकी

पिछले कई महीने से अमेरिका की ओर से लागू शुल्क नीति के कारण जहां दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, वहीं भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश करने की थी। अब सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उससे यही लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर हित पर आधारित एक समझौता आकार ले सकता है।ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका-भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत शुल्क को पचास फीसद से घटा कर अठारह फीसद किया जाएगा। दूसरी ओर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणा को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही है, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है।दरअसल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती और इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी रखी। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है। हालांकि भारत और रूस के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है।इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत कृषि जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है, लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। अतीत के भेदभाव को आधार बनाकर सवर्ण समाज के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को दंडित करने या आरक्षण जैसी नीतियों से बांधना न्यायसंगतता के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत योग्यता को नजरअंदाज कर सामूहिक दोषारोपण करता है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना दलित-ओबीसी नेतृत्व की न्यायसंगतता का तकाजा नहीं है!

अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना न्यायसंगतता का तकाजा नहीं?

(कमलेश पांडे)

लिहाजा, उन्मुक्त हृदय से उनके मौजूदा प्रगतिशील नेताओं को गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रतिगामी नजरिए को बदलकर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के राष्ट्रव्यापी लोकतांत्रिक भाव को मजबूत करना चाहिए। अन्यथा सामाजिक विघटन को परमाण्विक प्रक्रिया तेज होगी और इससे पैदा हुए जनविद्वेष की आग में देर-सबेर हरेक शांतिप्रिय लोगों के भी झुलसने का आसन्न खतरा बना रहेगा। ऐसा इसलिए कि यह नीतिगत, वैधानिक और रणनीतिक सवाल है जिसे कूटनीतिक स्वार्थवश विदेशों से हवा दी गई, इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे जातिविहीन हिंदुत्व के राष्ट्रवादी विचार को गहरा धक्का लगा है।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। इसलिए कहीं न कहीं यह सामाजिक एकता को कमजोर करता प्रतीत होता है। वहीं, जहां तक इस आशय की हुई क्षतिपूर्ति की अवधारणा की बात है तो यह अतीत-वर्तमान के अंतर्संबंध पर आधारित है, परंतु यह तब न्यायपूर्ण होती है जब यह पीड़ितों को शक्ति प्रदान करे, न कि नए भेदभाव को जन्म दे।

खासकर भारतीय संदर्भ में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी*ओबीसी) आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय सुधारने का ब्रितानी और भारत सरकार का विषैला सियासी प्रयास है, किंतु यूजीसी बिल (2026) जैसे नए प्रतिगामी नियमों व

कदमों के दुरुपयोग की आशंका पैदा करते हैं, जहां झूठे आरोप सामाजिक कड़वाहट बढ़ा सकते हैं। यह ठीक है कि रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसे मामले दर्दनाक हैं, लेकिन नीतियां ऐसी हों जो योग्यता और समावेश को प्राथमिकता दें।

ऐसा इसलिए कि एक तो छात्र राजनीति से पढ़ाई-लिखाई पर आंच आई, विश्वविद्यालय कैम्पस की गरिमा गिरी है और अब उन्हें जातीय नजरिए से बांटना आग से खेलने जैसा मूर्खता भरा सियासी कदम है। इससे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की तरह ही जातिवादी राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलेगा।

इसलिए बेहतर होगा कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करे। मेरे विचार से शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक उत्थान से भेदभाव दूर करना अधिक न्यायसंगत है, क्योंकि संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने से भविष्य स्वाभाविक रूप से समान बनेगा।

कहना न होगा कि अतीत को याद रखना जरूरी है, किंतु वर्तमान को उसके बोझ से मुक्त रखना ही सामाजिक प्रगति का आधार है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन्नावादी सांप्रदायिक सोच से निरंतर झुलस रहे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रितानी और अंबेडकरवादी/लोहियावादी जातिवादी सोच से विखंडित करने का जो मूर्खतापूर्ण सरकारी प्रयास जारी है, उससे जब सत्तर साल बाद भी मुट्ठीभर दलित-आदिवासी-ओबीसी की ही भलाई हो पाई है और उनमें भी नवसामंती भावना प्रबल हुई है, जिससे विखंडित जनादेश आने से अवसरवाद बढ़ा है। यह भारत के समावेशी विकास में भी अब बाधक बनता प्रतीत होता है।

यह ठीक है कि भारत में जातिगत भेदभाव के लिए

क्षतिपूर्ति मुख्यतः सकारात्मक कार्रवाई के रूप में लागू होती है, जो ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करती है। क्योंकि यह आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और विधायी सुरक्षा के माध्यम से कार्य करती है। इस हेतु संवैधानिक प्रावधान भी नियत हैं।भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, 16, 46 और 335 के तहत एससी/एसटी/ओबीसी को शिक्षा, नौकरियों और विधायी सुरक्षा प्रदान करता है, जो भेदभाव रोकने और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए हैं। वहीं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। जबकि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अपराधों पर दंड और पीड़ितों को राहत देता है।

आरक्षण सम्बन्धी प्रमुख नीतियां भी स्पष्ट हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण एससी को 15 प्रतिशत, एसटी को 7.5 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत कोटा नियत है। इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। उन्हें पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक और अन्य योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास और आवास योजनाएं (जैसे अंबेडकर आवास योजना) से भी उन्हें लाभान्वित किया जाता है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब सवर्णों को भी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन अन्य सहूलियत उन्हें मिलना अभी बाकी है। हालांकि, भारत की जातिवादी आरक्षण वाली सोच के समक्ष कुछ मजबूत चुनौतियां भी हैं। अगड़े भारतवासी इन्हें जाति की बजाए आर्थिक करने की मांग निरंतर करते आये हैं। वैश्विक नजरिए से भी ये नीतियां दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका जैसे देशों की क्षतिपूर्ति से भिन्न हैं, जहां प्रत्यक्ष आर्थिक मुआवजा दिया जाता है; जबकि भारत में फोकस सशक्तिकरण पर है, लेकिन इसके दुरुपयोग और सामाजिक तनाव की अकसर आलोचना होती है। सवाल है कि आखिर ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न क्या है? तो जवाब होगा कि ऐसे ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न से तात्पर्य उन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रियाओं से है जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जिनके कारण कुछ समूहों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया। यह अक्सर जाति, नस्ल, लिंग या धर्म जैसे आधारों पर आधारित होता है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं में निहित हैं। वहीं, उत्पीड़न इसके हिंसक या शोषणकारी रूप को दर्शाता है, जैसे बहिष्कार या हिंसा। इस प्रकार ऐतिहासिक भेदभाव किसी विशिष्ट विशेषता (जैसे जाति या नस्ल) के आधार पर समूहों के साथ जानबूझकर भिन्न व्यवहार है, जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में यह जाति व्यवस्था से जुड़ा है, जहां दलितों को मंदिर, पानी या शिक्षा से वंचित रखा गया था। भारत में इसके लिये अकसर सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों को आरोपित किया जाता है, जबकि सनातनी ब्राह्मणों ने तो उन्हें धार्मिक रूप से भी हिंदुत्व की माला में पिरोया है और उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की है। जबकि मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल में उनके हुए उत्पीड़न व शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि भारत सरकार में भी इस्लामिक व ब्रिटिश सत्तागत सोच वाली बुराइयों को निरंतरता प्रदान की गई है, जो बहस का विषय है। उदाहरणस्वरूप, जातीय उत्पीड़न को ही लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दलितों पर शारीरिक हिंसा, यौन शोषण या सामाजिक बहिष्कार, जो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा, निंदनीय है। वहीं, नस्लीय भेदभाव का भी यही आलम है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति या अमेरिका में रेडलाइनिंग, जहां नस्ल के आधार पर ऋण अस्वीकार किए गए। कुछ वैसा ही घटनाक्रम भारत में भी चला ब्रिटिश प्रभाव वश। वहीं, उपनिवेशिक प्रभाववश मुगलिया और ब्रिटिश राज में भारतीय अभिजात वर्ग को भी भेदभाव का शिकार बनाया गया, जो सामाजिक विषमता को गहरा करने वाला था। यह भेदभाव आज भी असमानता को बनाए रखता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार में अवसरों की कमी। कानूनी उपाय जैसे भारत का संविधान (अनुच्छेद 15, 17) इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में भेदभाव रोकने के लिए संविधान और विभिन्न कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं, खासकर जाति, नस्ल या लिंग आधारित ऐतिहासिक भेदभाव के खिलाफ। ये प्रावधान समानता सुनिश्चित करते हैं और दंडनीय अपराध बनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म-जाति-लिंग आदि पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सुनिश्चित करते हैं। वहीं, कुछ प्रमुख कानून भी बनाए गए हैं। जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955= अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय बनाता है। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989= अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त प्रावधान। इसी सिलसिले की अगली कड़ी लष्ट विनियम, 2026 है, जिससे उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के नए नियम बनाये गए हैं। जहां तक इनके कार्यान्वयन की बात है तो ये कानून अदालतों द्वारा लागू होते हैं, जैसे इंद्रा साहनी मामले में आरक्षण को मान्यता। शिकायत के लिए समर्पित सेल और पोर्टल उपलब्ध हैं। यूजीसी बिल पर भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश विचारणीय है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

गांव-गांव घूमकर भारत को समझते रहे मार्क टली

(राजेश प्रियदर्शी)

भारत में बीबीसी की पहचान रहे सर मार्क टली का जाना दुखद है। बीबीसी परिवार के लिए तो मानो पितामह के गुजर जाने जैसा है। मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे कई बार मिलने और बातें करने का अवसर मिला, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी ज्यादा खुशकिस्मत थी, जिसने उनको और ज्यादा करीब से, उनकी सक्रियता वाले दौर में देखा।

मार्क टली पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले तक हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका कॉलम देखकर यह आश्वस्ति होती थी कि वह ठीक हैं। उनसे सीखने लायक अनेक बातों में से एक बात तो यही थी कि मार्क टली हर किसी से, हर समय सीखते रहते थे। भारत के समाज और राजनीति की उनकी समझ बहुत गहरी थी, लेकिन वह अक्सर अपने वाक्य की शुरुआत कुछ यूं करते, 'मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, आप बताइए कि...।' जिन बातों की उन्हें पक्की जानकारी होती थी, उनके बारे में भी वह यही कहते थे, 'जहां तक मुझे मालूम है...।'

मुझसे कई बार वह झारखंड के बारे में पूछते थे। मार्क टली से बात करते हुए डर कभी नहीं लगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ज्ञान के आतंक की जगह विनम्र विद्वता की आभा थी, लेकिन इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहता था कि वह संथालों और मुंडाओं के बारे में उतना ही जानते थे, जितना उत्तर प्रदेश के निषादों और बिहार के मुसहरों के बारे में या फिर केरल के पानियन या मुथुवन लोगों के बारे में। उनकी किताब नो फुल स्टॉप इन इंडिया हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, जो भारत को गहरे समझना चाहता है। वह सबसे पहले अच्छी तरह यही समझाते हैं कि भारत समझ में क्यों नहीं आता? टली ने एक ब्रितानी अर्थशास्त्री के हवाले से कहीं लिखा था- 'भारत के बारे में जो आप सच कह सकते हैं, उसके ठीक विपरीत बात भी सच होती है।'

तकरीबन 90 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मे मार्क टली हर तरह से एक खांटी हिन्दुस्तानी थे। ज्यादातर समय खादी के कुरते और सैंडल पहनने वाले टली साहब लंबे समय तक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहे और धूप में घूमते रहने के कारण उनका गोरा रंग एक उम्र के बाद लगभग तांबई हो गया था। कोई अनजान आदमी उन्हें देखकर एकबारगी यह नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज हैं।

कई दशकों तक भारत और दक्षिण एशिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर शानदार पत्रकारिता करने वाले मार्क टली को आपातकाल के दौरान उनकी रिपोर्टिंग के कारण कुछ समय के लिए यहां से निकाल दिया गया था। वह लगातार निडर, लेकिन संतुलित पत्रकारिता करते रहे। मेरे बीबीसी पहुंचने से तीन साल पहले ही1994 में उन्होंने इस संस्थान से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह लगातार सक्रिय बने रहे। मार्क टली ने कोई दस किताबें लिखी हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और पठनीय हैं।

मेरी उनसे पहली लंबी बातचीत सन् 2001 के कुंभ मेले के दौरान हुई थी। तब उन्होंने बहुत विस्तार और गहराई से समझाया कि विदेशी लोग कुंभ मेले में क्यों खिंचे चले आते हैं? किसी भी विषय पर मार्क टली से बात करने का मतलब समझ की एक नई खिड़की का खुलना होता था। उन्होंने भारत को गांव-गांव घूमकर समझा था। वह हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते थे, जो उनको 'फर्स्ट हैंड' जानकारी दें। वह दिल्ली में संपादकों और बड़े पत्रकारों से जानकारी लेने में कम ही यकीन रखते थे। एक और बात, जो उन्हें विलक्षण बनाती थी, वह थी सहृदयता। मैंने कभी मार्क टली के मन में किसी के प्रति कटुता या दुराव का भाव नहीं देखा। उनको पसंद करने वालों की संख्या लाखों में थी, क्योंकि उन्हें नापसंद करने का कोई वास्तविक कारण खोजना मुश्किल काम था। मार्क टली को जैसी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा मिली, वह शायद ही किसी और पत्रकार को नसीब हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तित्व को सेलिब्रिटी होने की सहज संभावना से दूर रखा। मार्क टली से हर मुलाकात के बाद यह विस्मय रह जाता था कि वह इतने अद्भुत कैसे हैं? एक ऋषि जैसा जीवन जीकर विदा हुए सर मार्क टली को श्रद्धांजलि! (लेखक वरिष्ठ संपादक, बीबीसी हैं) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

सांसद निधि की तुलना दूसरी योजनाओं से नहीं हो सकती

सांसद स्थानीय विकास निधि को लेकर इन दिनों एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कुछ सांसदों के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने इस मद का एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इसी आधार पर कई लोग दलील दे रहे हैं कि इस योजना को ही खत्म कर देना जाना चाहिए, मगर सच यह है कि इसकी ऐसी उपयोगिता है, जिसकी विकास की अन्य योजना निधियों से तुलना नहीं की जा सकती। इसे व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसका कारण है। देश की आधारभूत संरचनाओं में प्रगति अब ठोस यथार्थ बन चुकी है। सड़क, पानी, बिजली, नाली, सीवर आदि जो कल तक स्थानीय लोगों की ज्वलंत समस्याएं हुआ करती थीं और लोग उसके समाधान की अपेक्षा सांसद-विधायक विकास निधि से रखते थे, वह बात अब प्रायः नहीं रही। पंचायत से लेकर जिले तक का बजट पिछले दस वर्षों में कई गुना बढ़ा है।

(राकेश सिन्हा)

यहां एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है। दुनिया के सभी पदों के पास घोषित शक्तियां होती हैं और पद के अनुपात में उनका विशेषाधिकार रहता है, परंतु सांसद के पास शक्ति शून्य है। वह जनता की वैधानिक ताकत से प्रतिनिधि बनता है, जनता के जीवन के सभी आयामों से उसका सरोकार होता है। अतः सांसद की ताकत विशेषाधिकार के गर्भ से उपजता है। सांसद निधि इसी विशेषधिकार को रेखांकित करता है।

इसके उपयोग में जितनी प्रयोगधर्मिता होगी, परिणाम उतने ही प्रभावी होंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे-से मुहल्ले (टोला) में सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये के लोग रहते हैं। युवाओं से संवाद में पुस्तकालय-निर्माण की मांग उठी। इसकी घोषणा करके राशि आवंटित कर देना एक मिनट का काम था। मैंने ऐसा नहीं किया। घंटों अनौपचारिक संवाद चलता रहा। उसी सिलसिले में टोले का जातिसूचक नाम बदलने पर राय बनी। नया नाम तय हुआ- हनुमान-शिव टोला। मैंने पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों

में पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण है। एक पुस्तकालय पीढ़ियों की सोच के निर्माण का पवित्र स्थल है, जहां अध्ययन, चिंतन, सृजन और संकल्प निर्माण होता है। पुस्तकालय भौतिकता, अनैतिकता, संकीर्णता आदि से उत्पन्न आपदाओं से समाज को बचाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, खेल के प्रति उन्होंने युवाओं में उत्साह बढ़ाया है। खेल में भी सुनहरा करियर है, गांव-कस्बों तक यह संदेश गया है। अतः खेल-सुविधाओं की भी मांग अब सांसदों से होने लगी है। चाहे निर्माण या विकास का रूप जो भी हो, इसमें बहुआयामी संवाद का जरिया बनने की असीम क्षमता है। सांसद निधि के साथ नैतिकता का आयाम लगते ही उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। एक तरफ, निर्माण कार्य होता है, दूसरी तरफ संकीर्णता की दीवार ढहने लगती है। सूची बनाकर विकास योजनाओं को जारी करना या मांग के आधार पर आवंटन की अपनी उपयोगिता है, पर वे जिलाधिकारी की योजना की तरह हो जाती हैं। उससे सांसद निधि का सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अंकुरित भी नहीं हो पाता है।

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में कोंगथोंग गांव को मैंने 2020 में गोद लिया था। सेंगखासी (जनजाति) का स्कूल सरकारी सहायता से वंचित था। सहायता देने से पूर्व लोगों के सामूहिक श्रमदान, स्वच्छता अभियान आदि पर संवाद होते रहे। ऐसे में, सांसद निधि स्कूल के विकास से अधिक वहां सामूहिकता के भाव को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गई। श्रमदान द्वारा निधि का उपयोग हुआ। सुखद बात यह रही कि ईसाई और सेंगखासी समुदायों के बीच चली आ रही कटुता मिट गई।

हमारे लोकतंत्र में एक कमी है, सांसदों के कार्यकलापों, विशेषकर सांसद निधि के उपयोग का सोशल ऑडिटिंग न होना। यह 'सब धान बाईस पसेरी' कर देता है। सोशल ऑडिटिंग से उनकी कमियों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ जनादेश नहीं है। इसकी बुनियाद में नैतिक व्यवस्था है। इसलिए सांसद निधि का उपयोग रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। (लेखक पूर्व सदस्य, राज्यसभा) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

संक्षिप्त समाचार

सड़क निर्माण के लिए भू-अर्जन हेतु समाघात दल ने की अनुशंसा

बिलासपुर। जिले के रतनपुर तहसील के ग्राम रतनपुर में हेलीपेड से बादल महल तक सड़क निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है। सामाजिक समाघात दल ने ग्राम रतनपुर में भू-अर्जन से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया। मूल्यांकन में पाया गया कि रतनपुर में भू-अर्जन से 0.12 एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है जिसका समाघात दल ने क्षेत्रवासियों से भी सहमति लिया और पाया कि अर्जित भूमि से कोई मकान आदि प्रभावित नहीं हो रहा है और न ही किसी भी परिवार के विस्थापन की संभावना है। सामाजिक समाघात दल द्वारा यह पाया गया है कि अधोसंरचना पर कोई बाधा नहीं है तथा अधोसंरचना का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। समाघात दल इस बात से संतुष्ट है कि लोक निर्माण विभाग को जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी ही भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। समाघात दल ने ग्राम रतनपुर में सड़क निर्माण हेतु रकबा 0.12 एकड़ भूमि का अर्जन लोकहित में किए जाने की अनुशंसा की है। रतनपुर में हेलीपेड से बादल महल तक सड़क निर्माण होने से रतनपुर के 5 वार्डों का आवागमन हेतु एक सुगम एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के समय यातायात को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए पहुंच मार्ग का उपयोग बायपास के रूप में हो सकेगा।

सुबह कमरे से नहीं निकली बेटी फंदे में लटक रही थी लाश

बिलासपुर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोन में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जब उनके घर की बेटी की लाश कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली. मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोन निवासी सुखीराम पटेल की 17 वर्षीय बेटी ईश्वरी पटेल की लाश रविवार की सुबह उसके कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली है. परिजनों के अनुसार सभी रात में खाना खाकर सो गए थे. सुबह 6 बजे जब परिजन सो कर उठे तो बेटी ईश्वरी का कमरा बंद था. परिजनों ने आवाज लगाई लेकिन कोई हलचल नही हुई तो खिड़की तोड़कर अंदर झांकते ही उनके होश उड़ गए. उनकी बेटी ईश्वरी पंखे में फांसी के फंदे पर झूल रही थी. जिससे पूरे परिवार में चींख पुकार मच गई. घटना की सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी गई, मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेज दिया. वही मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. फ्लिहाल युवती ने आत्महत्या क्यो की इसकी जानकारी सामने नही आई है. परिजनों ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक नही होने की जानकारी पुलिस को दी है

एसआईआर विवाद सुलझाः प्रशासन ने विलोपित सूची से हटाए नाम, मौन जुलूस स्थगित

कोरबा। एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में दिनांक 8-2-26 रविवार को दोपहर 3 बजे तहसील कार्यालय कोरबा में प्रशासन एवं सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची में नाम विलोपित किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रशासन द्वारा बैठक के दौरान संबंधित सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति का नाम विलोपित सूची में नहीं है तथा पूर्व में दर्ज सभी नाम विलोपित सूची से हटा दिए गए हैं। इस आश्वासन के बाद सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा ने प्रस्तावित मौन जुलूस को स्थगित करने की घोषणा की। प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज की सभी मांगों को स्वीकार कर समाधान का भरोसा दिया गया। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कोरबा सरोज महिलांगे, तहसीलदार बजरंग साहू, एडिशनल एसपी नीतीश कुमार ठाकुर, एडिशनल एसपी प्रतीक चतुर्वेदी, रामपुर चैकी प्रभारी नवीन पटेल, अजय सोनवानी,अजय सिंह परिहार, इमरान खान सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

सजग कोरबा-सतर्क कोरबा अभियान के तहत सख्त रात्रि चेकिंग

कोरबा। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा-सतर्क कोरबा अभियान के तहत 7-8 फरवरी की दरमियानी रात विशेष रात्रि चेकिंग एवं कांबिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर पूरे जिले में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान गुंडा व निगरानी बदमाशों की सघन जांच की गई। पूर्व से आदतन अपराधी पाए गए 12 लोगों पर धारा 129 बीएनएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 3 व्यक्तियों पर धारा 128 बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई हुई। वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

बिलासपुर जिले के 175 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न

■ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली जुड़कर नव दंपत्तियों को दिया आर्शीवाद

■ शासन की योजनाओं से निर्धन परिवारों को मिला संबल : श्री धरमलाल कौशिक

बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में किया गया। जिसमें 6 हजार 412 जोड़ों ने दांपत्य जीवन में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वर्चुअली जुड़कर सभी नव विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद दिया। इस अवसर पर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन स्व. श्री बी.आर. यादव बहतराई स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में जिले के 175 पात्र जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक सर्वश्री श्री धरमलाल कौशिक, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने दंपत्तियों को शुभकामनाएं दीं और उनके सुखद जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार निर्धन परिवार के बेटे और बेटियों की चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है और उनके एक बड़े दायित्व को सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने वर-वधुओं को आर्शीवाद देकर उनके सुखमय

जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सरकार न केवल गरीबों को घर दे रही है बल्कि शौचालय, पानी, बिजली की व्यवस्था सहित उन्हें प्रतिमाह खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रही है। रोजगार की उपलब्धता से उनके जीवन स्तर में सतत बदलाव आ रहा है। महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वरदान है। बहुत सारी बेटियों के हाथ आज पीले हो रहे हैं और मैं उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना करती हूं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याण योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकरात्मक बदलाव आ रहे है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए संवेदनशील पहल है। क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का यह भव्य आयोजन पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है, जिससे निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने बेटियों के विवाह को सम्मानजनक बनाया है। शासन की ओर से प्रत्येक हितग्राही जोड़े को 35 हजार रुपये का चेक उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। इसके साथ ही परिवहन हेतु 1 हजार रुपये की सहायता राशि तथा विवाह के लिए वस्त्र, मंगलसूत्र एवं श्रृंगार सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, बिल्हा जनपद अध्यक्ष श्री राम कुमार कौशिक, श्रीमती भारती माली, वंदना जेण्ड्रे सहित जिला व जनपद पंचायत बिल्हा के सदस्यगण उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, एसडीएम श्री मनीष साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी श्री सुरेश सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरूआत हुई

■ अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दवा का सेवन कर लोगों को किया जागरूक

बिलासपुर। जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत आज से कर दी गई है। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले के समस्त क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और दवा का सेवन कर बीमारी के प्रसार को रोकना है। आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सभी अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दवा का सेवन किया, ताकि आम जनता में जागरूकता बढ़े और लोग इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित हों। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन, एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने सभी लोगों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर दवा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि फाइलेरिया जैसे रोगों से बचाव केवल सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी घर-घर जाकर दवा का वितरण करेंगे और लोगों को रोग और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जो समय रहते रोकथाम के प्रयासों से नियंत्रित की जा सकती है। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में पूर्ण सहयोग दें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का दवा सेवन सुनिश्चित करें।

सीएमएचओ डॉ. एस. एन.केशरी ने करतला स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण

कोरबा। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एस.एन.केशरी लगातार मैदानी मोर्चे पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में डॉ. केशरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) करतला का सघन निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हर विभाग की हुई सूक्ष्म जांच डॉ. केशरी ने अस्पताल के चप्पे-चप्पे का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, ओपीडी, आईपीडी, प्रसव कक्ष, लेबर रूम, ओटी, दवा भंडार, इंटीग्रेटेड लैब और ब्लड स्टोरेज यूनिट सहित सभी महत्वपूर्ण कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए मुख्य द्वार पर पायदान लगाने और आईपीडी के बेडशीट की सफाई के लिए विशेष जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए:- आभा आईडी (आभा आईडी): ओपीडी में आने वाले हर मरीज की आभा आईडी सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान मित्र और मितानिन हेल्पडेस्क को सक्रिय करने को कहा। गर्भवती महिलाओं की देखभाल: सभी 'प्रायमी पारा' (पहली बार मां बनने वाली) महिलाओं को हाई रिस्क ग्रुप में रखकर उनकी विशेष जांच और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तकनीकी सतर्कता: शीत श्रृंखला में फ्रीजर के तापमान की निरंतर मॉनिटरिंग और ओटी में विसंक्रमण पर विशेष ध्यान देने को कहा। दवाइयों की उपलब्धता: खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि केंद्रों में सभी आवश्यक दवाइयों का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहे। डॉ. एस.एन.केशरी ने सख्त लहजे में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अनिवार्य रूप से मुख्यालय में ही निवास करें। उन्होंने जीवनदीप समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और आरबीएसके वाहनों का रिकॉर्ड अपडेट रखने के भी निर्देश दिए। हमारा लक्ष्य है कि जिले के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - डॉ. एस.एन.केशरी, सीएमएचओ, कोरबा

राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम : कोटा विकासखंड में सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया गया

बिलासपुर। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड कोटा में सामूहिक दवा सेवन अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत कोटा विकासखंड की कुल 3,08,113 जनसंख्या को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया गया। इसके लिए 550 दवा वितरण दलों का गठन किया गया है। अभियान के प्रथम चरण में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को बूथ बनाकर दवा सेवन कराया गया। इसके बाद 13 फरवरी से 22 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगी। वहीं, छूटे हुए लोगों के लिए 23 फरवरी से 25 फरवरी तक मॉप-अप राउंड चलाया जाएगा। इसी क्रम में आज कोटा विकासखंड के सभी पीएचसी एवं सीएचसी में भी अभियान की

शुरुआत की गई। विकासखंड स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शासकीय कन्या हाई स्कूल, पुरानी बस्ती कोटा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, विधायक प्रतिनिधि श्री प्रतीक त्रिवेदी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, विद्यालय की छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कर आमजन को जागरूक होने का संदेश दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि फाइलेरिया (हाथीपांव) एक गंभीर एवं लाइलाज बीमारी है, किंतु वर्ष में एक बार दवा का सेवन कर इससे पूरी तरह बचाव संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए।कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने फाइलेरिया मुक्त भारत के संकल्प के साथ अपने परिवार एवं आस-पड़ोस के लोगों को भी दवा सेवन कराने की शपथ ली। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. निखिलेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाला रोग है, जिसके लक्षण वर्षों बाद दिखाई देते हैं। ऐसे में बचाव ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि कोटा विकासखंड के हर घर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँचकर दवा वितरण सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, विधायक प्रतिनिधि प्रतीक त्रिवेदी, बीएमओ डॉ. निखिलेश गुप्ता, श्रीमती श्वेता सिंह बीपीएम, अतुल सिंह वीबीडीटीएस, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आशा दत्ता, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं व स्वास्थ्य विभाग का अमला , मितानिन कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

मामूली विवाद पर पत्नी की हत्या,पति गिरफ्तार

जशपुर। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में सब्जी पकाने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवति पत्नी की डंडे से मार-मारकर हत्या कर दी औश्र फिर अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्राम ढोठीपहरी, कुरूम ढोढा का है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.02.26 को प्रार्थी जेठू विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेलसुंगा थाना नारायणपुर के द्वारा थाना नारायणपुर में सूचना दिया गया था कि, उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा जो कि चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम ढोढ़ीबहार निवासी आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा से प्रेम करती थी, अत: कुछ वर्ष पूर्व वह, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा के पास रहने चली गई थी, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा, उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा को पत्नी बनाकर रखा था, वर्तमान में दोनों की एक दो वर्षीय बेटी है, व उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा 06 माह की गर्भवती थी, करीबन जनवरी माह से प्रार्थी की बेटी कमला व दामाद आरोपी स्वदेश, प्रार्थी के घर ग्राम बेलसुंगा में रह रहे थे, जहां आरोपी स्वदेश ग्राम रनपुर के एक व्यक्ति का ट्रेक्टर को चलता था,। घटना से तकरीबन 01 सप्ताह पूर्व, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा अपनी पत्नी कमला विश्वकर्मा व अपनी 02 वर्ष की बेटी को लेकर थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत ही ग्राम ढोठीपहरी, कुरूम ढोढा में अपने नाना के घर लेकर गया था व वहीं रह रहा था। घटना दिनांक 06.02.2026 को शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों पति पत्नि के मध्य सब्जी बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम ने आवेश में आकर, पास पड़े डंडे से अपनी पत्नि कमला के साथ मारपीट करते हुए उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे कि कमला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम अपनी 02 साल की बच्ची को लेकर वहां भाग गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर पुलिस के द्वारा मर्ग इंटीमेशन कायम कर, घटना स्थल के लिए रवाना होकर,शव पंचनामा की कार्यवाही की गई। घटना स्थल का फॉरेसिंक अधिकारी से निरीक्षण कराया तथा मृतिका के नवविवाहिता होने से दंडाधिकारी बगीचा से भी शव पंचनामा कराया। पुलिस के द्वारा मृतिका कमला विश्वकर्मा के शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्टम कराया गया। डॉक्टर के द्वारा शॉट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु का कारण मारपीट से आई चोट के कारण हत्यात्मक लेख करने पर पुलिस के द्वारा आरोपी स्वदेश उर्फसुदेश राम कोरवा के विरूद्ध थाना नारायणपुर में धारा 103(3) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था। थाना नारायणपुर पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी स्वदेश राम उर्फ सुदेश राम कोरवा की पता साजी करते हुए, उसे उसके गृह ग्राम ढोढीबहार चौकी दोकड़ा जिला जशपुर (छग) से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम ढोढ़ीबहार, चौकी दोकड़ा, जिला जशपुर (छ ग) के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयास अपराध सबूत पाए जाने से उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। व उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे को भी जप्त कर लिया गया है।

जनदर्शन में सुनी गयी लोगों की समस्याएं

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन एवं अपर कलेक्टर श्री एसएस दुबे ने भी लोगों की समस्याओं को सुना। लगभग 50-60 लोगों ने कलेक्टर से मिलकर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत धौराभाठा के सरपंच, सचिव सहित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष भवन अत्यंत

जर्जर हो चुका है। छत की प्लास्टर गिर रही है और बारिशों के दिनों में सीपेज की समस्या बनी रहती है। जिससे कभी भी दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो सकती है। कमिश्नर श्री सर्वे ने डीईओ को आवेदन की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। संत कबीरदास नगर वार्ड 11 के निवासी संजीव पाल ने वार्ड में रोड एवं नाली निर्माण के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि सड़कों में गड्ढों की वजह से दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है। बरसात के दिनों में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस मामले को नगर निगम आयुक्त देखेंगे। अग्निकांड से क्षतिग्रस्त आवास के लिए सहायता राशि दिलाने तालापारा निवासी श्यामकली खूटे ने गुहार लगाई। आगजनी की घटना से उन्हें आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण की जांच कर नगर निगम कमिश्नर उचित कार्यवाही करेंगे। मोपका वार्ड क्रमांक 48 के लोगों ने जोगनिन जोगिया तालाब में बिल्डरों द्वारा बाउन्ड्रीवाल कर देने के कारण तालाब में आने-जाने का रास्ता बंद होने की शिकायत की इस मामले को एसडीएम बिलासपुर देखेंगे। करबला रोड निवासी श्रीमती जबीन फातिमा ने आवास में दूसरी महिला द्वारा कब्जा करने की शिकायत की। इस मामले को नगर निगम आयुक्त देखेंगे। तखतपुर ब्लॉक के दर्री गांव निवासी श्री लल्लू राम केंवट ने जमीन का पुन: सीमांकन कराने आवेदन दिया। इस मामले को एसडीएम तखतपुर देखेंगे। शुभम विहार कॉलोनी निवासी श्री रमेश कुमार रावल ने वृद्धापेंशन फार्म जमा नहीं करने के संबंध में शिकायत की। उन्होंने बताया कि सर्वे सूची 2003 एवं 2011 में उनका नाम है लेकिन मेरा फार्म जमा नहीं लिया जाता है। इस मामले को नगर निगम आयुक्त देखेंगे।

सूने मकान में चोरी करने वाले मां-बेटे गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा की थाना कोतवाली पुलिस तथा पुलिस सहायता केंद्र की संयुक्त कार्यवाही में सूने मकान में चोरी करने वाले मां-बेटे को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके कब्जे से चोरी कर गिरवी रखे गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किये गये है।बता दें कि कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस सहायता केंद्र मानीकपुर / थाना कोतवाली कोरबा द्वारा सूने मकान में हुई चोरी की घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सफल खुलासा किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

प्राइवेट स्कूलों की स्थानीय परीक्षा डीईओ से लेने का निर्णय अव्यवहारिक

रायपुर। प्राइवेट स्कूलों की स्थानीय वार्षिक परीक्षायें डीईओ द्वारा कराये जाने के निर्णय को कांग्रेस ने अव्यवहारिक और अतार्किक निर्णय बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस, सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो अभी तक सरकारी स्कूलों की घरेलू परीक्षायें एक साथ तो आयोजित नहीं करवा पाता, घरेलू परीक्षायें स्कूल अपने स्तर पर करते है, ऐसे में वह प्राईवेट स्कूलों की परीक्षायें एक साथ कैसे आयोजित करेगा? सरकार पहले अपने सभी स्कूलों का सभी घरेलू परीक्षाओं को एक साथ आयोजित कर ले, उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के बारे में निर्णय ले। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि यह निर्णय भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से भी लिया गया है। सभी स्कूलों के प्रश्न पत्र छपाई और उत्तर पुस्तिका छपाई में घोटाला करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार सीबीएससी, आईसीएससी और भारती शिक्षा बोर्ड के स्कूलों को इस दायरे से बाहर क्यों रख रही है, सिर्फ स्थानीय बोर्ड से जुड़े स्कूलों पर यह व्यवस्था थोप कर उनको बंद करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है।

नक्सलवाद के खात्मे पर बोले विजय शर्मा- 31 मार्च से पहले पूरी जानकारी के साथ यह आखिरी बड़ी बैठक

रायपुर। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक शुरू हो गई है, जो देर शाम तक चलेगी। जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। वामपंथी उग्रवाद और संबंधित विभागों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरी जानकारी के साथ यह आखिरी बड़ी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में रायपुर में चल रही हाई लेवल बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए दो महत्व की बातें है, पहला 31 मार्च तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प हैं, सरकारों का उसके आधार पर क्या कार्ययोजना हो सकती है। कैसे सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो, और कैसे इस क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़े। दूसरा बस्तर के रुके हुए विकास का है, विकास के मार्ग कैसे होना चाहिए इसे समझते हुए लाइवलीहुड की दिशा से सोचना शुरू करेंगे। लाइवलीहुड के अवसंरचना है उसको लेकर चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद खात्मे की पूरी जानकारी के साथ 31 मार्च से पहले यह अंतिम बड़ी बैठक है, एसीएस होम कि संभवत 31 मार्च से पहले यह आखिरी बैठक हो सकती है, जिसमें रणनीतियों पर चर्चा होगी। जिसमें सभी प्रदेशों के बड़े डीजीपी समेत मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारी शामिल है। पहली बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। पहली विभागीय बैठक 11 बजे से 12:45 तक चलेगी, वहीं दूसरी विभागीय समीक्षा बैठक 12:45 से 2 बजे तक रहने वाली है। दोपहर 2 से 3 बजे तक भोजन का अवकाश रहेगा, जिसके बाद 3 बजे से 4:15 तक गृह मंत्री अमित शाह एलडब्ल्यूई क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री नक्सलवाद समेत कई सुरक्षा से जुड़े विषयों पर मंथन करेंगे। बैठक में केंद्र और राज्य के आला अधिकारी शामिल होंगे।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला समेत दो की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमेठी रोड स्थित बजरंग केमिकल कंपनी के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गुल्लू निवासी नन्द कुमार लोधी अपनी मां राजकुमारी लोधी और सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य डोमार सिंह लोधी की मां कुंती बाई लोधी को बाइक पर बैठाकर आरंग में एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर वापसी का यह सफर इतना भयावह होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अमेठी रोड मोड के पास सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही और अत्यधिक रफ्तार से वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर दूर जा गिरे और उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से घायलों को तत्काल शासकीय अस्पताल आरंग पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कुंती बाई लोधी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, नन्द कुमार और राजकुमारी लोधी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल रायपुर रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान एक युवक ने भी दम तोड़ दिया। आरंग पुलिस ने फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

ओवरब्रिज के नीचे चल रहा था 'नशे का सौदा', वेस्ट जोन पुलिस की दबिश से 20.300 किलो गांजा समेत अंतर्राज्यीय तस्कर दबोचा

रायपुर। नशे के सौदागरों के लिए रायपुर की धरती अब सुरक्षित नहीं रही। पुलिस कमिश्नरेट के सख्त तेवर और वेस्ट जोन पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। लालपुर ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने गांजा की डिलीवरी की फिराक में खड़े तस्करों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि चालक सीट पर बैठे तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम हिमांशु केशरवानी, निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) बताया। तलाशी के दौरान स्विफ्ट कार से अलग-अलग पैकेटों में भरा 20.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी ओडिशा के कालाहांडी से गांजा लाकर रायपुर और उत्तर प्रदेश में उसकी सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने न सिर्फ गांजा, बल्कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए, जिनकी कुल कीमत करीब 7 लाख 55 हजार रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के दिशा-निर्देश और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन में की गई।

छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा शैक्षिक संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह आयोजित

शासकीय विद्यालय संस्कार एवं सामाजिक सद्भावना के केंद्र-गजेंद्र यादव

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन के तत्वावधान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रेक्षागृह में भव्य शैक्षिक संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव थे। समारोह की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा ने की। कार्यक्रम में रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. शैलेंद्र पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने उपस्थित प्राचार्यगणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय विद्यालय बच्चों में संस्कार, समानता और सामाजिक सद्भावना के केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ गरीब-अमीर तथा समाज के सभी वर्गों के बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में संसाधनों के अभाव के बावजूद शासकीय विद्यालयों में नामांकन अधिक था, किंतु आज पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी नामांकन में निरंतर गिरावट शिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए चिंतन का विषय है। श्री यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में पदोन्नति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है, जो निरंतर जारी रहेगी तथा शिक्षकों की जायज़ मांगों पर समयबद्ध एवं सार्थक निर्णय लिए जाएंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा ने कहा कि समय के साथ समाज में शिक्षकों के सम्मान की भावना में परिवर्तन आया है। पहले शिक्षक समाज में सर्वोच्च सम्मान का पात्र होता था, किंतु आज स्थिति बदली है। उन्होंने शिक्षकों से समय के प्रति पाबंद रहते हुए पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया। रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने अपने रोचक उद्बोधन से उपस्थित

प्राचार्यगणों को खूब हंसाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के कारण मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्र रायपुर उत्तर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉ. शैलेंद्र पटेल ने कहा कि पदोन्नति के बाद भी प्राचार्यों को अध्यापन कार्य से जुड़े रहना चाहिए तथा नियमित रूप से कम से कम दो कालखंड पढ़ाना चाहिए। प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक श्री अनिल शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन में सभी पदोन्नत प्राचार्यों को बधाई दी। उन्होंने पदोन्नति प्रक्रिया में संचालनालय से न्यायालय तक संघर्ष में साथ देने वाले साथियों, मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बीते छह माह में 2800 प्राचार्य, व्याख्याता सहित लगभग 10,000 शिक्षकों एवं प्रधानपाठकों की पदोन्नति पारदर्शिता के साथ की गई है। प्रदेश के प्राचार्यों को एक मंच पर लाने हेतु छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन को फर्म्स एवं सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से श्री अनिल शुक्ला को पुनः प्रांतीय संयोजक चुना गया। शैक्षिक संगोष्ठी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव एवं उनकी टीम द्वारा छात्रों में मानसिक दबाव एवं अवसाद विषय पर व्याख्यान तथा जागरूकता आधारित टेलीफिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रिंसिपल एसोसिएशन के नौ सूत्रीय मांग पत्र का वाचन श्री राकेश शर्मा द्वारा किया गया। अतिथियों का शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया।

कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के बजाय अपराधियो का गैंग बनकर रह गई है-दीपक

रायपुर। संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने दुर्ग जिले में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में एनएसयूआई पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र पर तीखा हमला बोला है। दीपक ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों की आपराधिक वारदातों में संलिप्तता एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर रही है कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के बजाय अपराधियों, माफ्यिाओं और भ्रष्टाचारियों का गैंग बनकर रह गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक की होटल में लात-घूँसों से जमकर पिटाई करके अधमरा कर बाहर फेंक दिया गया ता। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पैसे नहीं लौटाने और फोन नहीं उठाने पर गुस्से में आरोपियों ने युवक को मार डाला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 26 जनवरी को हत्या का मामला दर्ज किया। जाँच के दौरान 27 जनवरी को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एनएसयूआई का जिला संयोजक प्रशांत राव और लक्की उर्फ किशन कुमार ध्रुवे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दीपक ने प्रदेश में अपराधों को लेकर प्रलाप कर रही कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में घट रहे अधिकांश अपराधों में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता सामने आने के बाद अब कांग्रेस को पहले अपने गिरेबाँ में

झाँकना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भूपेश सरकार के कार्यकाल में तो अपराध की हर विधा ने छत्तीसगढ़ को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम किया ही, आज विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस के लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, अपितु प्रदेश में अराजकता फैलाने के षड्यंत्रों का एजेंडा भी चला रहे हैं। दीपक ने कहा कि कांग्रेस का पूरा राजनीतिक चरित्र ऐसे हिंसक अपराधों से दागदार रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कॉस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का कांग्रेस के कई नेताओं के साथ फोटो है वहीं, हत्याकांड में शामिल एक आरोपी एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष था। इसी प्रकार छात्रा से दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने भानुप्रतापपुर निवासी एनएसयूआई छात्र नेता रूहाब मेमन को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने कहा कि कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने पुलिस को कानून-व्यवस्था के काम से हटाकर दीगर ऐसी करतूतों को अंजाम देने में लगा दिया था।

एलोवेरा आधारित पर्सनल केयर उत्पादों से पहचान बना रहा दुगली का वन धन विकास केंद्र

■ आदिवासी महिलाएं बनी आत्मनिर्भर

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत जिला धमतरी के ग्राम दुगली में स्थापित वन- धन विकास केंद्रआज महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का सफल उदाहरण बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में संचालित यह केंद्र वनोपज के मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को रोजगार और सम्मानजनक आय प्रदान कर रहा है। दुगली वन धन विकास केंद्र के स्व-सहायता समूहों के संघ के रूप में कार्य कर रहा है। एक प्रमुख समूह संचालन की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि अन्य समूह आवश्यकता और ऑर्डर के अनुसार उत्पादन कार्य में सहयोग करते हैं। केंद्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है। केंद्र में वर्तमान में लगभग 25 विभिन्न प्रकार के औषधीय और खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें हर्बल पाउडर, स्वास्थ्य पेय और अन्य हर्बल उत्पाद शामिल हैं। सभी उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बनाए जाते हैं तथा आयुष और खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त हैं। विशेष रूप से एलोवेरा से तैयार साबुन, क्रीम, बॉडी वॉश और हैंडवॉश जैसे पर्सनल केयर उत्पादों ने बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण, मशीनरी सहायता, ब्रांडिंग और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके परिणामस्वरूप उत्पाद राज्य स्तरीय मेलों, विभागीय नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुँच रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र का वार्षिक कारोबार 74 लाख 62 हजार 156 रुपए दर्ज किया गया, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ हर्बल' ब्रांड के अंतर्गत तैयार उत्पाद अब विभिन्न मार्ट, चयनित आउटलेट्स और ऑनलाइन माध्यमों पर उपलब्ध हैं तथा आयुष विभाग और पर्यटन मंडल को नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। दुगली वन धन विकास केंद्र आज केवल एक उत्पादन इकाई नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सामाजिक बदलाव की प्रेरक कहानी बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि शासकीय योजनाओं और सामूहिक प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया जा सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

खादी,हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है-केएस चौहान.....

रायपुर। संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल एक रणनीतिक कदम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 'आत्मनिर्भरता' और 'वैश्विक प्रतिस्पर्धा' की ओर ले जाने का लक्ष्य रखती है। यह पहल मुख्य रूप से खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल पाँच प्रमुख क्षेत्रों में निहित है। वैश्विक बाजार

जुड़ाव के जरिए ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य लोकल टू ग्लोबल के सपने को साकार करना है। गुणवत्ता और आधुनिकीकरण पर जोर देकर कारीगरों को आधुनिक मशीनरी, तकनीक और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूंजीगत सहायता दी जाएगी। इसमें 'चैलेंज मोड' में मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना भी शामिल है। कौशल विकास पर काम करके ग्रामीण युवाओं और बुनकरों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए 'स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग' और 'स्किलिंग' पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद बना सकें। इसी प्रकार यह पहल सरकार की 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडी-ओपी) योजना के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों को एक नई पहचान और सप्लाई चेन मिल सके।

कबीरधाम की महिला तीन बच्चों संग लापता, मायके जाते समय रास्ते में गायब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक महिला के अपने तीन बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे परिजनों में चिंता और बेचैनी बढ़ गई है। महिला पांडातराई क्षेत्र से अपने मायके बिलासपुर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वहां पहुंची ही नहीं। जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 15 निवासी बिसेन कार्निक (34 वर्ष) ने अपनी पत्नी पुष्पनंदनी कार्निक (26 वर्ष) और तीन बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे उनकी पत्नी बच्चों के साथ इलाज कराने बिलासपुर जाने की बात कहकर शारदा बस से रवाना हुई थीं। शाम करीब 6 बजे संपर्क करने पर महिला के दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले।

अब राजस्व सेवाएँ एक क्लिक दूर

भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा का हुआ शुभारंभ

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक सशक्त बनाते हुए आज नागरिक सुविधा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण और अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा तथा ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का औपचारिक राज्यव्यापी शुभारंभ किया। ये दोनों डिजिटल पहल राज्य में ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को अब राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कार्यवाही पूरी तरह सरल, तेज़ और पारदर्शी होगी। भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक अब अपने मोबाइल फोन पर ही विभिन्न राजस्व सेवाओं की जानकारी और सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सीधे शासन से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है, जो राज्य की डिजिटल रूपांतरण यात्रा को नई गति प्रदान करेगी। इस चैटबॉट सेवा के अंतर्गत नागरिकों को जमीन संबंधी जानकारी, राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा, आधार नंबर जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन, किसान किताब हेतु आवेदन, नामांतरण हेतु आवेदन सहित अन्य नागरिक हितैषी राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे केवल एक व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से ले सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिक +91 7289056060 नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेज सकते हैं, जिसके पश्चात चैटबॉट तुरंत आवश्यक जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने एक और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का भी

शुभारंभ किया। यह सुविधा भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब नागरिक बिना किसी कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाए अपने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर भूमि चयन से लेकर प्रीमियम एवं शुल्क की गणना तक की पूरी प्रक्रिया स्वचालित और सहज बनाई गई है। भुगतान प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के साथ छह आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आवेदन जमा होते ही वह स्वत: संबंधित सक्षम अधिकारी के पास परीक्षण हेतु प्रेषित हो जाएगा। सक्षम अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा, जिससे अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगी। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होता है, तो नागरिक को डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वत: जारी कर दिया जाएगा, जिससे नागरिकों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी और शासन की जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी। नागरिक हितों की सुरक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिक द्वारा गणना की गई राशि वास्तविक देय राशि से कम पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। नागरिक को 60 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड का प्रावधान लागू होगा। इस अवसर पर राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले तथा संचालक राजस्व श्री विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। तकनीक के माध्यम से शासन को सीधे नागरिकों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, ताकि समय, संसाधन और श्रम की बचत हो तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मुरझाई तुलसी देती हैं संकट का संकेत

हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र पौधे का स्थान दिया गया है। इस धर्म से जुड़े लोगों के घर- आंगन में आपको तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिलेगा। लोग नियमित रूप से इसका पूजन करते हैं। तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जिस घर में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा होती है, वहां कभी धन-दौलत व सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती, लेकिन तुलसी से जुड़े कई नियम भी है जिन्हें मान्यताओं के अनुसार, मानना जरूरी भी है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी से जुड़े कुछ नियम ...

तुलसी को किस दिन नहीं छूना चाहिए?

तुलसी के पौधे को एकादशी, रविवार और चंद्र व सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं छूना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी तुलसी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं।

तुलसी माता को क्या चढ़ाया जाता है?

तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक पवित्र माना जाता है। घी की जगह सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।

तुलसी की मंजरी का क्या करना चाहिए?

तुलसी की पत्तियों के बीच के हिस्से को मंजरी कहते है। मंजरी तुलसी के पत्तों के बीच में से निकलती है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे से मंजरी उतार देनी चाहिए। इससे तुलसी का बोझ कम होता है। मंजरी उतारने को तुलसी की महा सेवा कहा जाता है। तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में या धन स्थान पर रख दें। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।

क्या तुलसी का पौधा उपहार में दे या ले सकते हैं?

तुलसी सबसे पवित्र और शुभ पौधों में से एक है जो घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए, पौधे को उपहार में देना एक बेहद शुभ माना जाता है लेकिन सुनिश्चित करें कि आप एक स्वस्थ पौधा उपहार में दें, सुखा तुलसी का पौधा ना उपहार में दें और ना लें।

तुलसी दोष कैसे दूर करें?

ऐसा माना जाता है कि तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आने वाले संकट का संकेत देता है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नजर, घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार, अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। जहां दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तुलसी दोष को दूर करने के लिए रोज सुबह तुलसी के पौधे एवं शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ है जिन्हें शालीग्राम भी कहते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे में शालीग्राम की मूर्ति या पत्थर रखने और उनकी नियमित पूजा करने से सारे दोष मिट जाते हैं।

तुलसी विवाह में गन्ना बहुत शुभ माना जाता है

तुलसी विवाह वाले दिन मां तुलसी को गन्ने से बनी खीर का भोग लगाएं। गन्ने को तुलसी विवाह में बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप फल और मिठाई का भोग लगा

घर की नेगेटिविटी दूर करेगा सेंधा नमक

खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत ही खास माना जाता है। इससे जुड़े उपाय घर में सुख-शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वैसे तो नमक कई तरह का होता है,परंतु सबसे ज्यादा जरुर सेंधा नमक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी इसका उपयोग घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए किया जाता है। इस शास्त्र के अनुसार, सेंधा नमक को बेस्ट क्लींजर के तौर पर माना जाता है,जो नेगेटिविटी दूर करता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि सेंधे नमक से जुड़े वास्तु टिप्स.....

मां लक्ष्मी का होगा वास

यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का घर में वास हो तो आप घर या फिर ऑफिस में सेंधा नमक डालकर पोंछा लगाएं। इससे नेगेटिविटी दूर होगी।

वास्तु दोष होगा दूर

घर में यदि वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए नैऋत्य कोण (दक्षिण पश्चिम) दिशा में कांच के बाउल में सेंधा नमक रखें। इससे वास्तु दोष दूर होगा।

नेगेटिव एनर्जी होगी दूर

यदि आपको थकान, आलस्य और दरिद्रता महसूस होती है और नेगेटिव विचार आते हैं,तो इसका अर्थ है कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास है। ऐसे में इसे दूर करने के लिए नहाने के पानी में सेंधा नमक डालकर नहाएं। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी।

घर में आएगी पॉजिटिविटी

यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास , तो आप घर के बाहर क्रिस्टल फॉर्म में नमक डालकर रख दें। इससे घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा।

इस दिन न खरीदें सेंधा नमक

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन सेंधा नमक नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।

बच्चों को डांटने के बजाय समझाना उचित

बच्चों की परवरिश करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें माता-पिता हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं। इस यात्रा में डांट-फटकार भी अनुशासन का एक साधन बन जाता है,लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बच्चों को डांटने का प्रभाव उनकी उम्र के साथ बदल सकता है? वास्तव में विशेषज्ञ कहते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद बच्चों को डांटना उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज हम जानेंगे कि किस उम्र के बाद अपने बच्चों को डांटना बंद कर देना चाहिए और क्यों?

बच्चों को कब नहीं डांटना चाहिए

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को खासतौर पर 7 से 8 साल की उम्र के बाद डांटने की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। इस उम्र के बाद, बच्चे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और उनकी सोच में परिपक्वता आने लगती है। इसलिए, उन्हें डांटने की बजाय, उनसे संवाद करना और समझाना ज्यादा उचित होता है।

डर की भावना पैदा होती है

बच्चों में डांटने का असर केवल उनके व्यवहार पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उनकी मनोवृत्ति और भावनाओं पर भी गहरा असर डालता है। जब बच्चों को बार-बार डांटा जाता है, तो इससे उनमें एक गहरी और लगातार डर की भावना विकसित हो सकती है। यह डर उन्हें अपने माता-पिता या अन्य वयस्कों के सामने खुलकर अपनी बातें कहने से रोकता है। वे सोचने लगते हैं कि अगर वे कुछ गलत कहेंगे या किसी गलती का इज़हार करेंगे, तो उन्हें फिर से डांट पड़ेगी। इस तरह की डर की भावना उनके विकास के लिए हानिकारक है।

टीन एज में बच्चों से साथ दोस्ती करें

टीन एज, यानी किशोरावस्था, बच्चों के विकास का एक नाजुक दौर होता है। इस समय में बच्चे खुद को और अपने आस-पास की दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए, इस उम्र में उन्हें डांटना बंद कर देना चाहिए। बजाय डांटने के उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी बातों को सुनना और समझाना ज्यादा कारगर होता है। ऐसा करने से वे अपनी समस्याओं को खुलकर बता पाएंगे और समाधान की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस दौरान, उन्हें प्यार और समर्थन की जरूरत होती है,ताकि वे जिम्मेदारी के साथ अपने निर्णय ले सकें और अपनी पहचान को मजबूती से विकसित कर सकें।

मेकअप के आसान उपाय

वर्किंग वूमेन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। उन्हें ऑफिस के साथ-साथ घर के भी कामों पर भी ध्यान देने होता है। सुबह-सुबह इतना समय नहीं होता है कि आराम से तैयार हो पाएं। कपड़े पहनने के साथ ही आपको ब्रेकफास्ट भी करना होता है या फिर दूसरे कामों को करते हुए ऑफिस भी जाना होता है। ऐसे में कई महिलाएं मेकअप करने से भी बचती ही हैं, लेकिन इससे आप ऑफिस में pre-sentable नहीं लगती हैं तो क्यों न बस 5 मिनट निकालकर फ्लॉलेस मेकअप किया जाए। जी हां, ये बहुत ही आसान है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में...

फाउंडेशन के साथ सनस्क्रीन

सबसे पहले आपको स्किन पर फाउंडेशन के साथ सनस्क्रीन मिलाकर लगाना है। ये आपकी स्किन में थोड़ा लाइट के साथ धूप के नुकसानों से भी बचाने में भी मदद करेगा।

जेल या क्रीम वाला फाउंडेशन

आप प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन के साथ सनस्क्रीन मिलाकर लगाना ज्यादा सही है। कोशिश करें कि इसके लिए जेल या क्रीम वाला फाउंडेशन का इस्तेमाल करें।

आई लाइनर

आई लाइनर से आंखों को बड़ा ही आकर्षक लुक मिलता है। इससे आंखों की खूबसूरती बढ़ जाती है और चेहरा काफी फ्रेश लगता है। आप काजल भी अप्लाई कर सकती हैं।

लिपस्टिक

डार्क शेड की लिपस्टिक लगाने पर चेहरे को ग्लैमरस लुक मिलता है। आप न्यूड या पीच कलर की लिपस्टिक से क्लासी लुक भी पा सकती हैं।

ब्लश एंड हेयर

इसके बाद अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने और मेकअप को बैलेंस करने के लिए लाइट कलर का ब्लश लगा सकती हैं। वहीं बालों को जल्दी-जल्दी में स्टाइल करना मुसीबत का काम लग रहा है,तो इसे स्ट्रेट कर लें या फिर नीट बन बना लें। बस इस स्टेप्स के साथ आप परफेक्ट मेकअप करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं।

मिट्टी के बर्तनों में दही जमाने के फायदे

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दही को मिट्टी के बर्तनों में जमाना बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। यहां कुम्हार मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाते थे। जिसमें दही जमाया जाता था ,लेकिन यह परंपरा अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है,लेकिन मिट्टी के मटके या कुल्लड में जमे दही खानें का मजा ही कुछ और होता है। मिट्टी के बर्तनों में जमा दही अपनी विशिष्ट गंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। मिट्टी में मौजूद खनिज तत्व दही को एक स्वाद देता है। मिट्टी हमेशा ठंडी रहती है जिससे दही काफी देर तक ठंडा और कसावट वाला बना रहता है और यह दही खानें में जितना ज्यादा लजीज होता है उतना ही फायदेमंद भी, आइए जानते हैं मिट्टी के बर्तनों में जमे दही के फायदे...

स्वाद

मिट्टी के बर्तनों में जमे दही का स्वाद अनूठा होता है और इसमें मिट्टी की गंध का प्रभाव होता है, जिससे दही का स्वाद और गंध बहुत ही अच्छा होता है।

मिनरल

मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। जब हम दही को मिट्टी के बर्तनों में जमाते हैं, तो ये खनिज मिट्टी से दही में स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे दही में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये दही को और भी पौष्टिक बना देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।

एल्कलाइन

मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे एल्कलाइन तत्व पाए जाते हैं। जब दही को मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है, तो ये एल्कलाइन तत्व मिट्टी से दही में ट्रांसफर हो जाते हैं।ये एल्कलाइन तत्व शरीर के pH लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं और कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

प्रोबायोटिक

मिट्टी में कई प्रकार के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब हम दही को मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स मिट्टी से दही में स्थानांतरित हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हमारे आंतों में स्वस्थ बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।

सौंफ खाने के फायदे

सौंफ एक बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा है। इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसके तेल का इस्तेमाल स्किन और हेयर केयर में होता है। सौंफ कैंसर, मधुमेह और ह्रदय रोगों से लड़ने में मददगार होता है। इसके अलावा सौंफ में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी आदि भी पाए जाते हैं। जो स्वास्थ्य के फायदेमंद होता है। यहां जानते हैं,सौंफ कैंसर के खतरा को कैसे कर सकता है कम ...

<u>एंटीऑक्सीडेंट गुण</u> :- सौंफ एक प्राकृतिक मसाला है,जो अपने स्वाद और सेहत संबंधित लाभ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो मुक्त रैडिकल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। मुक्त रैडिकल्स शरीर के कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। सौंफ के एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे एक स्वास्थ्यवर्धक आहार में शामिल करने का कारण बनते हैं, जो शरीर को संरक्षण प्रदान करता है और बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। मुक्त रैडिकल्स से उत्पन्न होने वाले क्षति को रोकना शरीर में कैंसर का जोखिम कम कर सकता है।

<u>एस्ट्रोजन की अनुकरणीयता</u> :- सौंफ में फाइतोएस्ट्रोजन होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। यह गुण स्तन कैंसर जैसी कुछ प्रकार की कैंसर से बचाव में सहायक हो सकता है। सौंफ के इस गुण का सही तरीके से उपयोग करने पर कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे कि पीएमएस (पूर्व-मासिक धर्म सिंड्रोम) के लक्षणों में सुधार।

<u>एंटी-इन्फ्लैमेटरी गुण</u> :- सौंफ में एंटी-इन्फ्लैमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और जलन को कम कर सकते हैं। यह शरीर में सूजन जैसी स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जो कैंसर का जोखिम बढ़ा सकती है।

<u>डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया</u> :- सौंफ जिगर के साथ अच्छी तरह काम करती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, जिससे जिगर के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। यह जिगर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, जो कैंसर का जोखिम कम कर सकता है।

दौड़ लगाना सेहत के लिए लाभकारी

धावकों को समय को लेकर जुनून होता है। शौकिया हों या पेशेवर, अधिकतर धावकों का उद्देश्य तेजी से दौड़ना होता है। वे अपने मैराथन समय में से कुछ सेकंड कम करने के लिए लगातार प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दौड़ने का जो चलन जोर पकड़ रहा है, वह है "धीमी गति से दौड़ना"। इस चलन के पीछे विचार यह है कि कोई भी दौड़ सकता है - चाहे आपकी क्षमता कुछ भी हो या आप कितनी भी तेज दौड़ें।

इसके हैं कई फायदे

इस दृष्टिकोण के विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कई फायदे हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह आपके दौड़ने को आनंददायक भी बनाता है। अनुसंधान भी इससे सहमत हैं और साक्ष्यों से पता चलता है कि धीमी गति से दौड़ना कुछ मायनों में तेज गति से दौड़ने की अपेक्षा अधिक फायदेमंद हो सकता है।

जब हम विशिष्ट धावकों के बारे में सोचते हैं, तो हम मान सकते हैं कि विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए, वे मुख्य रूप से इन कीर्तिमान गति पर प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट धावक प्रशिक्षण के दौरान अपना लगभग 80 प्रतिशत समय जोन-2 दौड़ में बिताते हैं।

इसमें दौड़ने की गति आपकी ह्रदय गति को बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी इतनी धीमी होती है कि आप बातचीत कर सकते हैं।

उनका लगभग 20 प्रतिशत प्रशिक्षण ही उच्च गति वाले दौड़ से संबंधित होता है। इसका कारण प्रशिक्षण की वजह से शरीर पर पड़ने वाले दबाव के स्तर से है।

धीमी गति से दौड़ने के ये हैं फायदे

यह महत्वपूर्ण है,क्योंकि ह्रदय की पंपिंग क्षमता प्रशिक्षण के अनुकूल हो जाती है, लेकिन उच्च तीव्रता इस लाभ को नहीं बढ़ाती है। एक मजबूत आधार विकसित करने से काम करने वाली मांसपेशियों को प्रति धड़कन अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता मिलती है,जो दौड़ में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बल्कि धीमी गति से दौड़ने से शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहीत वसा का इस्तेमाल करता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट संग्रह पर निर्भर रहने के विपरीत है। शरीर में एकत्र वसा का खंडित होना चयापचय की दृष्टि से कहीं अधिक कुशल प्रक्रिया है, क्योंकि वसा के एक अणु से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा से कहीं अधिक होती है। इसका मतलब है कि धावक कुल मिलाकर कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे और कम थकेंगे तथा दौड़ के दिन तेजी से दौड़ने में सक्षम होंगे। अध्ययनों में खुलासा हुआ है कि अधिक समय तक धीमी गति से दौड़ने वाले एथलीटों के लिए वीओ2 (ऑक्सीजन क्षमता) अधिकतम और गति में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अधिक तेजी से दौड़ने वाले एथलीटों की तुलना में धीमी गति से दौड़ने वालों का 'एरोबिक आधार' लगभग पांच गुना अधिक होता है। भले ही आप एथलीट न हों फिर भी अपने अधिकांश दौड़ की तीव्रता कम रखना श्रेष्ठ होता है।

क्यूआर कोड स्कैन कर ग्रामीणों को कार्यों की मिल रही जानकारी, विकसित भारत वीबी जी राम जी योजना के प्रावधानों से कराया अवगत

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनाया गया रोजगार एवं आवास दिवस

जांजगीर-चांपा । जांजगीर-चांपा जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में 7 फरवरी को रोजगार दिवस के साथ-साथ आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विकसित भारतङ्कवीबी जी राम जी योजना के प्रावधानों से अवगत कराया गया। रोजगार दिवस का आयोजन कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करना तथा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर त्वरित निराकरण करना रहा।रोजगार दिवस के अवसर पर जिले के समस्त मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों को योजना से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से श्रमिकों को पूर्व में स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों के बारे में अवगत कराया गया।आवास दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को नवीन स्वीकृत आवासों के स्वीकृति जानकारी के साथ ही किए गए तथा निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों से संबंधित तकनीकी, प्रशासनिक एवं भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। विशेष रूप से ई-केवाईसी, लंबित किश्तों का भुगतान तथा मनरेगा से अभिसरण के अंतर्गत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी भुगतान से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया गया। आयोजन से पूर्व ग्राम पंचायत एवं विकासखंड स्तर पर तकनीकी स्टाफ की बैठक आयोजित कर मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित तकनीकी विषयों का निराकरण सुनिश्चित किया गया, जिससे कार्यक्रम के दिन हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम के दौरान आजीविका डबरी, तालाब, कुआं, सोख्ता गड्ढा, गहरीकरण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन कार्यों की जानकारी दी गई।

प्रत्येक आवास के समक्ष सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु हितग्राहियों को प्रेरित किया गया। साथ ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विकसित भारतङ्कवीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिवस रोजगार की गारंटी, 7 दिवस में मजदूरी भुगतान, अधोसंरचना निर्माण एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इसके लिए आईईसी गतिविधियाँ, पोस्टर-पाम्पलेट वितरण एवं चौपाल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि रोजगार दिवस एवं आवास दिवस के इस एकीकृत आयोजन से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित सेवाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।

अवरीद भाटापारा में अखंड नवधा रामायण का भव्य शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

जांजगीर-चांपा । जिले के गौरव ग्राम पंचायत अवरीद भाटापारा में 7 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले श्री अखंड नवधा रामायण पाठ का शुभारंभ कलश यात्रा एवं भव्य शोभायात्रा के साथ हुआ। धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ, यह भव्य कलश यात्रा नवधा स्थल से मोहल्ला से प्रारंभ हुई। यात्रा का मार्ग आस्था का केंद्र रहा, जिसमें माताएं और बहनें बड़ी संख्या में शामिल हुईं। शोभायात्रा में ठाकुर देव तालाब से जल भरकर भाटापारा स्कूल, मोहल्ला से गुजरते हुए पुनः अखंड नवधा रामायण पंडाल के पास अपनी यात्रा पूरी की।कलश यात्रा के दौरान माताएं और बहनें पारंपरिक वेशभूषा में मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय निवासियों ने जगह-जगह

कलश यात्रा का स्वागत किया और पूजा-अर्चना की। श्री अखंड नवधा रामायण पाठ, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान किया जाएगा। यह आयोजन क्षेत्र में धार्मिक चेतना और एकजुटता का प्रतीक है। अखंड नवधा रामायण के दौरान प्रतिदिन मानस मंडलियों द्वारा राम कथा का मधुर गायन एवं प्रवचन किया जाएगा, जिसमें आस-पास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

कलेक्टर ने की अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट प्रगति की समीक्षा

अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शत-प्रतिशत आधार अपडेट सुनिश्चित करें : कलेक्टर

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिप्स विभाग की बैठक लेकर अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट की प्रगति की समीक्षा की।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक आधार अपडेट सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का आधार नामांकन अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित प्राचार्य/प्रधान पाठक को पालकों एवं विद्यार्थियों को रोस्टर अनुसार कम से कम एक-दो दिन पूर्व आधार शिविर में आधार कार्ड सहित उपस्थित होने के लिए पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक दिवस की रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ने निर्देश दिए आधार अद्यतन का कार्य आधार केंद्र संचालकों द्वारा यूआईडीएआई द्वारा

निर्धारित मानकों के तहत करें। कलेक्टर ने आधार अपडेट कार्य को पूरी गंभीरता से करते हुए यू-डाइस पोर्टल में समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने कहा कि जिले के स्कूलों में मेंडेटरी बायोमेट्रिक आधार अपडेशन हेतु विद्यार्थी समूह 5ङ्क7 वर्ष एवं 15ङ्क17 वर्ष के लिए 7 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक विशेष आधार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आधार सेवा केंद्र के माध्यम से आधार बनवाते हुए यू-डाइस पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित की जाए। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाए, ताकि किसी भी विद्यार्थी का डेटा अपूर्ण न रहे। बैठक में कलेक्टर ने अपार आईडी कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यकता अनुसार विशेष शिविरों का आयोजन करने निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि समस्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।बैठक में वनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुनील कुमार साहू, पोस्ट ऑफिस आईपीपीबी से नीरज कुमार सहित सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, सीडीपीओ एवं जिले के समस्त आधार ऑपरेटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

जैविक खेती अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम

वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल की टीम ने छात्र-छात्राओं को दी जैविक खेती की जानकारी

जांजगीर-चाम्पा। बहेराडीह गांव में स्थित देश के पहले वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल द्वारा जैविक खेती अभियान चलाया जा रहा है. किसान स्कूल की टीम द्वारा गांवों की चौपाल, स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं को जैविक खेती के लाभ और रासायनिक खाद के नुकसान से अवगत कराया जाता है. इस दौरान सभी को जैविक खेती के महत्व से अवगत कराकर जागरूक किया जाता है. इसी के तहत किसान स्कूल की टीम, कुटरा गांव के पं. रामसरकार पांडेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची और 'जैविक खेती अभियान' के तहत छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल बहेराडीह के संचालक दीनदयाल यादव ने छात्र-छात्राओं को जैविक खेती के हर पहलू से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज जैविक खेती बहुत आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक खाद के अंधा-धुंध इस्तेमाल से उत्पादित खाद्य पदार्थों में भी रासायनिक खाद का प्रभाव रहता है और इसका असर

लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. जैविक खेती से इन सभी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ, मानव शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है. इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने जैविक खेती को लेकर सवाल भी पूछे, जिसका किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने सार्थक जवाब देकर छात्र-छात्राओं को संतुष्ट किया। इस मौके पर नवाचारी किसान रामाधार देवांगन ने छात्र-छात्राओं को वेस्ट से बेस्ट के बारे में बताया और किसान स्कूल बहेराडीह में किए गए अनोखे नवाचार केले की शाखा के रेशे और भिंडी, अलसी, अमारी भाजी के डंठल के रेशे के साथ ही इससे बने कपड़ों के बारे बारीकी से जानकारी दी। यहां इन नवाचार को छात्र-छात्राओं देखा तो वे हैरत में पड़ गए और इन नवाचार को जानने उनकी जिज्ञासा बढ़ गई. इस पर रामाधार देवांगन ने रेशे निकालने और कपड़ा बनाने में होने वाली प्रक्रिया के बारे में भी बताया। इस दौरान किसान स्कूल के सदस्य राजकुमार साहू ने किसान स्कूल की स्थापना, किसानों को नि:शुल्क ट्रेनिंग और अनेक नवाचार के साथ ही 'जैविक खेती अभियान' के उद्देश्य के बारे में बताया. यहां पराली नहीं जलाने और जल संरक्षण का भी संदेश दिया गया. साथ ही, जैविक खेती अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने की भी अपील की गई। कार्यक्रम में पत्रकार हिमांशु साहू, स्कूल के प्राचार्य संदीप श्रीवास्तव, अनुराग तिवारी व्याख्याता, अवधेश शर्मा, महावीर विजर्सन, श्रीमती काजल कर, उमेश चौबे, दीनानाथ उपाध्याय, खिलेंद्र तिवारी, कमल किशोर कौशिक, श्रीमती नीलिमा पाठक, श्रीमती चंद्रावती रात्रे, श्रीमती काजल कहरा, सुरेश कुमार हंस, शेखर साहू, हेमेश्वर नर्मदा, मकरम कमलाकर, भृत्य संदीप कश्यप मौजूद थे।

कुंभ कल्प मेला के आठवें दिन राजिम कुंभ कल्प में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़, मेले की बढ़ी रौनक

गरियाबंद। राजिम कुंभ कल्प मेला की रौनक अपने चरम पर पहुंच गई है। माघ पूर्णिमा 1 फरवरी से प्रारंभ हुए राजिम कुंभ कल्प मेला के आठवें दिन रविवार को त्रिवेणी संगम एवं नवीन मेला मैदान में श्रद्धालुओं और मेलार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण अन्य दिनों की तुलना में भीड़ कहीं अधिक रही, जिसकी झलक शनिवार से ही देखने को मिली। देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर भगवान श्रीराजीवलोचन एवं पंचमुखी कुलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन किए। इस दौरान संगम तट से लेकर मेला क्षेत्र तक श्रद्धा, आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कुंभ कल्प मेला क्षेत्र में त्रिवेणी संगम स्नान, मंदिर दर्शन, लक्ष्मण झूला, मीना बाजार, सांस्कृतिक मंच, मुख्य महोत्सव मंच, संभागीय सरस मेला, चारधाम यात्रा, राम वनगमन पथ, शासकीय स्टॉल, साधु-संतों की कुटिया, यज्ञशाला एवं भोग-भंडारा श्रद्धालुओं के प्रमुख आकर्षण बने रहे। दिनभर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में घूमते नजर आए और जमकर खरीदारी भी की। राजिम कुंभ कल्प मेला तीन जिलों की

सीमा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। लोमस ऋषि आश्रम के समीप कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर क्षेत्र में धमतरी जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्टॉल लगाए गए हैं, जहां राज्य शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इसी तरह रायपुर एवं गरियाबंद जिलों द्वारा भी विभिन्न विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र में एक हजार से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। त्रिवेणी संगम से लेकर नवीन मेला मैदान चौबेबंधा राजिम तक फैले मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में भी सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। राजिम कुंभ कल्प मेला में इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तीन अलग-अलग मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वहीं नवीन मेला क्षेत्र के स्थानीय मंच और पुराने महोत्सव स्थल नदी मंच पर प्रदेश के कलाकार छत्तीसगढ़ की लोककला, लोकगीत, लोकसंगीत और लोकनृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कलाकारों को मिल रहे उत्साहपूर्ण प्रतिसाद से मेला परिसर उल्लास से सराबोर नजर आ रहा है। त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन भव्य महानदी महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसे गंगा आरती के नाम से भी जाना जाता है। साध्वी प्रज्ञा दीदी के मुखारविंद से प्रतिदिन शाम 7 बजे महाआरती संपन्न हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जिससे मेला क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और अधिक प्रबल हो गया है। नवीन मेला मैदान में इस बार दो स्पेशल मीना बाजार लगाए गए हैं, जो मेलार्थियों के लिए विशेष आकर्षण बने हुए हैं। लगभग 8 एकड़ में फैले मीना बाजारों में आकर्षक झूले, क्राफ्ट बाजार, मौत का कुआं, जलपरी शो, जंगल के जानवरों की प्रदर्शनी एवं वैष्णोदेवी झांकी लोगों को खासा लुभा रही है। वहीं आजीविका मिशन के तहत आयोजित संभागीय सरस मेला में बिहान समूह की दीदियों द्वारा शुद्ध एवं ताजा सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। जिले के महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। बिहान दीदियों का कहना है कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।

1 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से पचराही बोदा सड़क निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन

कवर्धा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 77 लाख 99 हजार रुपये की लागत से पचराही से बोदा तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। यह सड़क क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ विकास की नई राह खोलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू एवं पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू की गरिमामयी उपस्थिति में विधिवत पूजा-अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे, रामकिंकर वर्मा, जनपद उपाध्यक्ष नंद श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य रूपसिंह धुर्वे, नितेश अग्रवाल, मोहनसिंह धुर्वे, कांशीराम उइके, अमित वर्मा, नंदे पटेल, नरेश चंद्रवंशी, विश्वनाथ मेरावी, हरिचंद मेरावी, रमेश मेरावी, उर्मिला साकत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा

विधायक विजय शर्मा के कुशल नेतृत्व में जिले में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। गाँव से लेकर शहर तक अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़े-बड़े कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जिले को नई दिशा मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में घोटिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि पचराही-बोदा सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुँचाने में आसानी होगी तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस सड़क के निर्माण से पचराही, बोदा सहित आसपास के गांवों के लोगों को वर्षभर सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में लगातार विकास कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल रहा है।

जिले में कुल 53 लाख 01 हजार 950 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी

किसानों को 1256 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ भुगतान

मुंगेली । शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले के 105 उपार्जन केन्द्रों में सुव्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिले के 66 समितियों के 105 खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों की संख्या 01 लाख 10 हजार 900 से अधिक है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत 15 नवंबर से 30 जनवरी तक तथा दिनांक 05 और 06 फरवरी को जिले में कुल 53 लाख 01 हजार 950 क्विंटल से अधिक धान की गई, इसमें मोटा 29 लाख 22 हजार 180 क्विंटल, पतला 330 क्विंटल

और सरना 23 लाख 79 हजार 430 क्विंटल धान शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संवेदनशील पहल पर किसानों को 05 और 06 फरवरी को भी धान बेचने की सुविधा प्रदान की गई। किसानों को 1256 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।

कबीरधाम में कानून बेदम, अवैध ईंट भट्ठा माफिया बेखौफ

शहर,गांव,जंगल तक फैला गैरकानूनी कारोबार, बिना लाइसेंस चल रहे सैकड़ों भट्ठे, जिम्मेदार विभागों की रहस्यमयी चुप्पी

कवर्धा। कबीरधाम जिला इस समय अवैध ईंट भट्ठा माफिया के चंगुल में फंसा नजर आ रहा है। शहर, गांव और संरक्षित जंगल क्षेत्रों तक बिना किसी वैध अनुमति के ईंट भट्ठे धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन कानून लागू कराने वाली मशीनरी पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रही है। जिले में संचालित अधिकांश ईंट भट्ठों के पास न खनिज विभाग का लाइसेंस है, न पर्यावरणीय स्वीकृति और न ही वैध रजिस्ट्रेशन, इसके बावजूद खुलेआम उत्पादन और बिक्री जारी है। यह हालात साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संरक्षण और मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं।

बिना रॉयल्टी कोयला, जंगल की लकड़ी से जल रहे भट्ठे

सूत्रों के अनुसार भट्ठों में बिना रॉयल्टी का कोयला, इमरती लकड़ी तथा फलदार और हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जंगल उजड़ते जा रहे हैं और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है।

कार्रवाई सिर्फ कागजों में

जब भी शिकायत सामने आती है, तो संबंधित विभागों द्वारा औपचारिक जांच, खानापूर्ति वाली कार्यवाही और दिखावटी नोटिस जारी कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है। किसी बड़े भट्ठा संचालक पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

जवाबदेही तय होगी या नहीं

सबसे बड़ा सवाल यह है कि खनिज विभाग वर्षों से आंख मूंदे क्यों बैठा है। वन विभाग जंगलों में हो रही अवैध कटाई से अनजान कैसे। पर्यावरण विभाग और जिला प्रशासन आखिर किस दबाव में खामोश हैं। क्या यह मान लिया जाए कि अवैध ईंट भट्ठा माफिया को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। पर्यावरण और भविष्य से खिलवाड़, जंगल क्षेत्रों में फलदार और इमरती पेड़ों की कटाई से वन्यजीव, भूजल और पर्यावरण संतुलन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

जनता में उबाल

इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों, किसानों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यदि अब भी जिम्मेदार अधिकारियों और अवैध भट्ठा संचालकों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन तय है। अब सवाल साफ है – कबीरधाम में शासन चलेगा या अवैध ईंट भट्ठा माफिया का राज।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com